● वर्ष-4
● अंक-98
रायपुर, मंगलवार
03 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

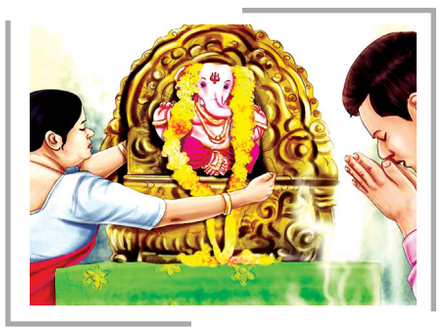

पेज-6» ऐसे कीजिए प्रार्थना ईश्वर जल्द सुनेंगे...

अब जनता चुनेगी महापौर

निकायों और पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब नगर पालिका निगमों के महापौर और नगरीय निकायों के पंचायत अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाएगा। यह निर्णय आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार ने ये चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का निर्णय लिया था। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष

विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का निर्णय

का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

हितग्राहियों को मिलेगा उच्च क्वालिटी का चना- मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, ई-आक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई. छत्तीसगढ़ सरकार की चना वितरण योजना के माध्यम से हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदाय किया जा सके, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को ई-आक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई.

पर्यटन को उद्योग का दर्जा- मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है.

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक, जल पर्यटन, मेडिकल एवं वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाईयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी. इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे. पर्यटन संबंधी अधोसंरचना का विकास होगा. पर्यटन से संबंधित पूंजी निवेश बढ़ेगा.

नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण

छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है.

देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री!

4 दिसंबर को होगी घोषणा, शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू

मुंबई। वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी के हवाले से बताया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की पूर्व संध्या पर, बुधवार 4 दिसंबर को की जाएगी। पदाधिकारी ने कहा कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करने के बाद आएगा। भगवा पार्टी ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किया, जहां विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे।

गुजरात के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने कहा कि पार्टी ने हम दोनों को महाराष्ट्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हम पर्यवेक्षक के रूप में जा रहे हैं जहां विधायक दल के नेता की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। केंद्रीय कार्यालय हमें बैठक की तारीख बताएगा और हम जाकर सभी से मिलेंगे और फिर आलाकमान से बात करेंगे। हाईकमान की बात मानें तो विधायक दल के नेता की घोषणा कर दी जायेगी। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सोमवार को घोषणा की कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे।

भाजपा ने कहा कि मेरी राय है कि फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। बीजेपी कोई आश्चर्य नहीं देगी। सुधीर मुनगंटीवार ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे इस फैसले से नाराज नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि अगर किसी विभाग को लेकर आपकी अपनी मांगें हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नाराज हैं। वह सभी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। शिंदे का सम्मान किया जाएगा। मुझे लगता है कि शिंदे भी सरकार का हिस्सा होंगे। जनता ने महायुति को भारी मतों से जिताया है।

इंडिया गठबंधन में दरार!

कांग्रेस के एजेंडे से टीएमसी का किनारा

नई दिल्ली। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दलों के भीतर एक महत्वपूर्ण दरार उभरी है। इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और कांग्रेस सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर असहमत हैं।

सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, टीएमसी ने अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के एकाकी ध्यान केंद्रित करने पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। टीएमसी का मानना है कि विपक्ष को वह अन्य मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो लोगों के लिए अधिक प्रासंगिक हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग नहीं लिया। टीएमसी ने छह प्रमुख मुद्दों की रूपरेखा तैयार की है जिन्हें वह सत्र के दौरान उठाना चाहती है- मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, उर्वरक की कमी, विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों को धन की कमी और मणिपुर में जारी हिंसा। टीएमसी नेताओं का तर्क है कि ये मुद्दे सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण बकाया जारी नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की है, जो अधूरे जीएसटी हस्तांतरण के साथ-साथ 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी अदानी समूह के खिलाफ आरोपों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियोग के दावों पर संसद में तत्काल चर्चा के लिए दबाव डाल रही है।

मंत्रियों संग मोदी ने देखी 'द साबरमती रिपोर्ट'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और फिल्म कलाकारों के साथ साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में भाग लिया। यह फिल्म 2002 में गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस कोच को जलाने पर आधारित है। मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम ने स्क्रीनिंग से तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में साथी एनडीए सांसदों के साथ शामिल हुआ। मैं फिल्म के निर्माताओं की उनके प्रयास के लिए सराहना करता हूं।

अभिनेता जीतेंद्र ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को बताया कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल बिताए हैं और अपनी बेटी की वजह से पहली बार मैंने पीएम के साथ फिल्म देखी है। पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली फिल्म देख रहा हूं। बीजेपी सांसद मयंक नायक ने कहा कि फिल्म ने सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का काम किया है। सच्चाई को हराया नहीं जा सकता। पीएम मोदी, गुजरात सरकार की छवि खराब करने की कई कोशिशें की गईं। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद लोगों को सच्चाई और पीएम मोदी, गुजरात सरकार की छवि खराब करने की साजिशों के बारे में पता चलेगा...पीएम मोदी का नेतृत्व और गुजरात की जनता निर्दोष निकली है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। यह हमारे देश का इतिहास है और पिछली सरकार ने लोगों से तथ्य छिपाए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि उस समय ऐसी गंभीर स्थिति में लोगों ने कैसे राजनीति की।

प्रमुख समाचार

महाराष्ट्र का सीएम तय करने सीतारमण और विजय पर्यवेक्षक नियुक्त

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के सीनियर नेता विजय रूपाणी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस निर्मला सीतारमण और भाजपा के सीनियर नेता विजय रूपाणी पर्यवेक्षक में ही ऐलान किया जाएगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए ही निर्मला सीतारमण और भाजपा के सीनियर नेता विजय रूपाणी पर्यवेक्षक होनी है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि 4 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की मीटिंग की जाएगी, जिसमें किसी एक नेता का नाम प्रस्तावित किया जाएगा और फिर से सभी विधायकों की मंजूरी ली जाएगी। फिलहाल यही चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम ही भाजपा हाईकमान की ओर से प्रस्तावित किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा कोई खुलकर इस मसले पर बोल भी नहीं रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे पूरा जोर लगा रहे हैं कि यदि वह सीएम नहीं बनाए जा रहे हैं.

हमने आपको जमानत दी और अगले दिन आप मंत्री बन गए!

नई दिल्ली। डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद तमिलनाडु सरकार में मंत्री बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों पर दबाव बनाने की आशंका जताने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी। हालांकि, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बालाजी को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 26 सितंबर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बालाजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि, हमने आपको जमानत दी और कुछ दिनों बाद आप मंत्री बन गए। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि अब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में गवाहों पर दबाव होगा। ये क्या हो रहा है? न्यायमूर्ति ओका ने आगे कहा कि अदालत जमानत के फैसले पर कोई नोटिस जारी नहीं करेगी, लेकिन इस पर सुनवाई होगी कि क्या अब गवाहों पर दबाव होगा। पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की है।

प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से 'सुप्रीम' सवाल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेकर सोमवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरएपी के चौथे चरण का शायद ही कोई कार्यान्वयन हो रहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रतिबंधों को लागू करने, खास तौर पर ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए कितने अधिकारी तैनात किए गए हैं? मामले में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह जीआरएपी प्रतिबंधों का पालन न करने के आरोपों की जांच करेगी। सिर्फ दो या तीन घटनाओं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 1.5 करोड़ की आबादी वाला पूरा शहर नियमों का पालन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के प्रतिबंधों में ढील देने से पहले प्रदूषण में कमी आनी चाहिए। कोर्ट ने एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होकर यह बताने को कहा कि निर्माण श्रमिकों को मुआवजा दिया गया है या नहीं? अब दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिव पांच दिसंबर को कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होंगे.

भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। हालांकि अभी तक पुतिन के दौरे की तारीख तय नहीं है। रूसी राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योते पर भारत आ रहे हैं। रूसी दूतावास ने यह जानकारी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता यूरी उशाकोव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे नेता की साल में एक बार बैठक करने का समझौता है। इस बार हमारी बारी है। हमें प्रधानमंत्री मोदी का न्योता मिला है और हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगले साल की शुरुआत में कोई तारीख तय हो सकती है। रूस और यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद यह व्लादिमीर पुतिन का पहला भारत दौरा है। इस वजह से पुतिन का यह दौरा बेहद अहम है, खासकर तब, जब भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने की अपील की है। रूस और भारत के बीच इसके शीर्ष नेताओं द्वारा हर साल एक दूसरे देश के देश का दौरा करने पर सहमति बनी हुई है। इसी सहमति के तहत पुतिन का भारत दौरा हो रहा है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा किया था। उल्लेखनीय है कि अगले साल क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत का दौरा करेंगे।

अंतरिक्ष में 'ट्रैफिक जाम' का खतरा, सूरज की रोशनी पर भी असर!ष्ट

नई दिल्ली. धरती की निचली कक्षा (लोअर अर्थ ऑर्बिट-एलईओ) में बढ़ते सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष के कचरे की वजह से एक बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर स्थिति इसी तरह बढ़ी रही, तो इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसके चलते न सिर्फ अंतरिक्ष मिशनों को मुश्किलें आएंगी, बल्कि सूरज की रोशनी भी पृथ्वी पर सही तरीके से नहीं पहुंचेगी। अभी तक, इस निचली कक्षा में 14 हजार से ज्यादा सैटेलाइट्स और लगभग 12 करोड़ अंतरिक्ष कचरे के टुकड़े मौजूद हैं। इनमें से साढ़े तीन हजार सैटेलाइट्स तो अब बेकार हो चुके हैं। इस स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष मामलों के पैनल ने चिंता जताई है और कहा है कि देशों, कंपनियों और कार्पोरेट्स को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स की डायरेक्टर आरती होला-मैनी ने कहा कि अंतरिक्ष के कचरे और सैटेलाइट्स की संख्या इतनी बढ़ गई है कि भविष्य में इनका टकराव हो सकता है, जिससे धरती पर भी नुकसान हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन सैटेलाइट्स और कचरे को साफ नहीं किया गया, तो स्पेस मिशन को बेहद गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है।

जीत और गठबंधन की मृगमरीचिका में आखिर कब तक भटकेगी कांग्रेस?

कमलेश पांडे

कांग्रेस एक पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसका देशव्यापी जनाधार है। लेकिन वह जीत और गठबंधन की मृगमरीचिका में आखिर कबतक भटकेगी, यह एक यक्ष प्रश्न है? आखिर कमजोर %सियासी बैशाखियों% के सहारे उसकी जीत कितना मुकम्मल कहलाएगी और स्थायी बन पाएगी, यह उससे भी ज्यादा विचारणीय पहलू है! वैसे भी जब कांग्रेस विभिन्न महत्वपूर्ण राज्यों में क्षेत्रीय दलों की वैशाखी ढूंढ़ती है या फिर मुद्दों के बियाबान में भटकती और फिर स्टैंड बदलती नजर आती है तो मुझे इसके रणनीतिकारों पर तरस आती है।

ऐसा इसलिए कि मैंने भू-जमींदारी देखी है, जहां पर लोग अपनी जमीनें ठेके या बंटाईदारी पर देकर अनाज और पैसे दोनों लेते हैं। ठीक उसी तरह से आज कांग्रेस के रसूखदार और धन्नासेठ नेता पार्टी संगठन में पद और चुनावी टिकट देने के वास्ते %वोट% और पैसा दोनों लेते/लिवाते हैं, यह जानते हुए भी कि सामने वाला न तो उनका जनाधार बढ़ा पाएगा और न ही चुनाव जीत/जीतवा पाएगा। ऐसा वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि सामने वाला अमीर है, वफादार है, पिछलग्गू भर है या फिर निहित समीकरण वश किसी ने उसकी सिफारिश की है। बेशक कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन वही जिनके नेहरू-गांधी परिवार से ठीकठाक सम्बन्ध हैं।

अब बात पते की करते हैं। जैसे एक शातिर बंटाईदार अपने भूस्वामी की भूमि पर भी कब्जा कर लेता है और इसमें जब वह असफल होता है तो जमीन मालिक से कम कीमत में उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहता है। अनुभवहीन भूस्वामियों को ऐसा करते हुए भी देखा सुना है। ठीक इसी प्रकार लालू प्रसाद और स्व. मुलायम सिंह यादव जैसे नवसियासी बटाईदारों ने कांग्रेस के साथ किया और आज क्षेत्रीय सियासी जमींदार बन बैठे हैं। ऐसा इसलिए सम्भव हो सका, क्योंकि निहित स्वार्थवश पीवी नरसिम्हाराव यही चाहते थे! उनके तिकड़म को सोनिया गांधी नहीं समझ सकीं!

वहीं, आज जब राहुल-प्रियंका गांधी की कांग्रेस की रीति नीति देखता हूँ तो इनकी राजनीतिक जमींदारी के हश्र को महसूस भी करता हूँ। कांग्रेस माने या न माने, लेकिन समाजवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादी सियासी जमींदारों ने उसकी राजनीतिक जमींदारी को क्षत-विक्षत करने में अहम भूमिका निभाई है और हैरत की बात यह है कि वह समझ नहीं पाई और नादान बनी रही। जबकि इसके खिलाफ ठोस और जमीनी रणनीति बनानी चाहिए। जैसे कि उसके बाद जन्मी भाजपा ने किया है।

माना कि सत्ता प्राप्ति के लोभ में क्षेत्रीय दलों से गठबंधन यानी यूपीए/महागठबंधन की सोच तो सही है, लेकिन इनके इशारे पर कांग्रेस संगठन को हांकना कतई सही नहीं है। कांग्रेस इससे इंकार कर सकती है, लेकिन वह आज इसी की पूरी सियासी कीमत अदा कर रही है। आज वह सत्ता में नहीं है, फिर भी उन्हीं लोगों से सहारा ढूंढ रही है, जो उसकी सियासी पतन के लिए कसूरवार हैं। चूंकि मैंने एआईसीसी/बीजेपी/तीसरे मोर्चे को कवर किया है, इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के अंग्रेजी भाषी दलाल नेताओं ने उसके जमीनी नेताओं को भाजपा या क्षेत्रीय दलों में जाने के लिए अभिशप्त कर दिया।

चूंकि कांग्रेस के जमीनी नेताओं के पास रणनीति और जनाधार दोनों है, इसलिए वो अपने व्यक्तिवादी मिशन में सफल रहे, लेकिन कांग्रेस दिन ब दिन डूबती चली गई। राजनीतिक परिस्थिति वश कभी दो डग आगे तो चार कदम पीछे चलने को अभिशप्त हो गई। इस बात में कोई दो राय नहीं कि किसी भी स्थापित दल को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लायजनरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनके निहित स्वार्थों के ऊपर यदि ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार रखने वाले नेताओं की उपेक्षा की जाएगी तो फिर वोट कहाँ से आएगा, यह सोचने की फुर्सत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास नहीं होगी।

अतीत पर नजर डालें तो एक जमाना था जब गांव-गांव में कांग्रेस के मजबूत शुभचिंतक थे, लेकिन पार्टी की अव्यवहारिक रीति-नीति के चलते वह इससे दूर होते चले गए। दो टूक कहें तो भाजपा में या क्षेत्रीय दलों में शिफ्ट हो गए। ऐसे में आज कांग्रेस के पास सिर्फ उन %धनपशुओं% की टोली बची है, जिनको दूसरी राजनीतिक पार्टियां कभी तवज्जो नहीं देतीं। इनका काम कांग्रेस की सत्ता और संगठन के बड़े नेताओं के शाही खर्चों का इंतजाम करना भर है और इसलिए इनके समर्थक ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय संगठनों पर हावी हैं।

चूंकि इनका कोई जनाधार नहीं है और ये जनाधार वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते, इसलिए कांग्रेस खत्म होती चली गई। वहीं, जब से क्षेत्रीय कांग्रेस के नेता अस्तित्व रक्षा के लिए बिहार में राजद प्रमुख लालू प्रसाद व तेजस्वी यादव तथा उत्तरप्रदेश में सपा प्रमुख स्व. मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जैसे मजबूत नेताओं के इशारे पर काम करने लगे, तब से पार्टी संगठन की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। आलम यह है कि कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी, जिसे देश की आजादी का श्रेय प्राप्त है, जब जनजीवन व राष्ट्रीय हितों से इतर प्रमुख जातीय, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय समीकरणों पर खेलने लगी, तो उसकी जोड़-तोड़ से सत्ता तो बदलती रही, परंतु जनाधार छीजता चला गया। क्योंकि उसके प्रति निष्ठावान रहे प्रतिभाशाली पेशेवर, कारोबारी, प्रशासक और समाजसेवी आदि उससे दूर होते चले गए। चूंकि पहले क्षेत्रीय दलों और उसके बाद भाजपा ने उन्हें तवज्जो दी, इसलिए वो सब इनके साथ जुड़ गए, जिससे इन्हें अप्रत्याशित मजबूती मिली और कांग्रेस को कमजोरी मुबारक हुई।

शहर बंद और सड़कों पर उतरे व्यापारी

■ न्यायालय को बाहर शिफ्ट किए जाने का विरोध

बालोद। छत्तीसगढ़ का बालोद शहर सोमवार को पूरी तरह बंद था। यहां पर सभी व्यापारिक संगठनों ने बंद कहा आह्वान कराया है, सुबह से ही व्यापारी कुछ खुले दुकानों को बंद करने निकले हुए थे परंतु शहर के सभी छोटे बड़े व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है। दरअसल बालोद शहर में बरसों से बना जिला एवं सत्र न्यायालय को अब बालोद शहर के समीप ग्राम पंचायत सिवनी में स्थानांतरित किया जा रहा है जिसका विरोध व्यापारी कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले भी कलेक्ट्रेट परिसर को संयुक्त जिला कार्यालय को बालोद शहर से बाहर सिवनी गांव में ही बनाया गया है और जो प्रमुख शासकीय भवन है जैसे यातायात कार्यालय एवं अन्य कार्यालय यह सभी शहर से बाहर जा रहे हैं। जिसके कारण व्यापारियों के व्यापार पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर बालोद बंद का आव्हान आज किया गया है।

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष राजू पटेल ने बताया कि धीरे-धीरे षडयंत्र पूर्वक बालोद शहर से सभी शासकीय कार्यालय को ले जा रहे हैं ले जाया जा रहा है इसके कारण जो छोटे बड़े व्यवसाय हैं सभी को संघर्ष से जूझना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि आज व्यापार की हालत काफी खराब है और यदि एक कार्यालय न्यायालय के रूप में जो बालोद में बना है उसे भी बाहर ले जाया गया तो हमें भीख मांगनी पड़ सकती है वही तो कपड़ा व्यापारी अमित चोपड़ा ने बताया कि हम एक व्यापारी हैं व्यापार की हालत हम देख रहे हैं सभी लोन लेकर व्यापार करते हैं ऐसे में जो शहर की रौनक जो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी तो सभी व्यापारियों को अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है उन्होंने कहा कि हम सब प्रशासन की इस फैसले को अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे।

आगे अनिश्चितकाल बंद होगा शहर

चार बार के पार्षद रहे कमलेश सोनी ने कहा कि प्रशासन का जो रवैया शहर वासियों के साथ है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यदि हफ्ता भर के भीतर यहां पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो बालों शहर को भी निश्चित कालीन बंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज हम सब भाजपा और कांग्रेस सहित आम जनता व्यापारी सभी ने स्वार्थ रूप से सभी के हित के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं शहर में घूम रहे हैं लोगों को जागरुक कर रहे हैं आज बंद का आव्हान किया था वह भी काफी सफल रहा है।

वहीं व्यवसाय कांतिलाल जैन ने बताया कि यहां पर व्यापार ठंडा पड़ रहा है हम नहीं प्रतिष्ठान डालते भी हैं तो व्यापार काफी मंद गति से है ऐसे में एक किसका कार्यालय के जाने से तो और काफी फर्क इस शहर के व्यापारियों को पड़ेगा इसके साथ ही दौलत राम ने बताया कि एक-एक बजे तक हम होटल व्यवसाई हैं बोहनी हुए रहता है अगर इसी तरह व्यापार चलते रहा तो हमें कुछ और करना पड़ेगा लेकिन हम शुरू से ही व्यापार से जुड़े हुए हैं हमें और कोई काम नहीं आता प्रशासन को व्यापारियों के भी चिंता करनी चाहिए आखिर हम भी उन्हीं के ही प्रशासन और सरकार का एक हिस्सा है।

हाथियों ने मचाया तांडव, 50 से 55 हाथियों का झुंड कर रहा विचरण

■ पांच मवेशियों को उतारा मौत के घाट

कोरबा। कोरबा के वनांचल क्षेत्रों में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज में एक बार फिर से हाथियों की वापसी हो गई है,जिससे ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। सिर्री पंचायत से सटे जंगल में पिछले दो दिनों से जंगली हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है और जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने जहां पांच मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया वहीं किसानों की धान की फसल और बाड़ियों में लगी सब्जियों को भी रौंद दिया।

जंगली हाथियों के कारण कोरबा के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। हाथियों की आमदगी के कारण ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर है। एक महिने के बाद कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज में हाथियों की वापसी ने वन विभाग के साथ ही ग्रामीणों को सकते में डाल दिया है। सिर्री पंचायत से सटे जंगल में पिछले दो दिनों से हाथियों का दल डेरा डाल रखा है। बीती रात हाथियों ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने बहारपारा निवासी गोविंद सिंह के पांच मवेशियों का मार दिया। इतना ही नहीं खेतों में लगी धान की फसल को चौपट करने के साथ ही बाड़ी में लगी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के उत्पात में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें,कि इस ईलाके में करीब 55 हाथियों का दल विचरण कर रहा है जिससे ग्रामीण काफी दहशत में है,लेकिन वन विभाग हाथियों को खदेड़ने को लेकर किसी करत का ध्यान नहीं दे रहा।

वहीं वन विभाग को भी इस घटना की जानकारी दी गई जहां हाथियों पर नजर रखी हुई है और ग्रामीणों को हाथियों के पास जाने से मन कर रहे हैं वहीं आसपास हाथी प्रभावित गांवों में मुनादी कराई जा रही है। इसके अलावा किसानों के जो फसल,मकान नुकसान हुए है और मवेशी की मौत हुई है उसका प्रकरण बनाकर आगे की कार्यवाही करने में जुटी हुई है।

5वीं सीनियर स्टेट ओपन वुडबॉल चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

गरियाबंद। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक गरियाबंद जिले के पंडुका में आयोजित 5वीं सीनियर स्टेट ओपन वुडबॉल चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से खेल जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस चैंपियनशिप में मिक्स डबल्स के मुकाबले में श्रृंगी शर्मा और चंचल खुंटे की जोड़ी ने अपनी रणनीति, धैर्य और कौशल का उत्कृष्ट परिचय देते हुए कांस्य पदक हासिल किया। इस जोड़ी ने शुरुआती दौर से ही अपना वर्चस्व दिखाया और कठिन मुकाबलों में अपनी जगह बनाते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया।

टीम इवेंट में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। बलौदा बाजार के लड़कों की टीम ने अपने दमदार खेल और बेहतरीन तालमेल के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी जीत इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वहीं, लड़कियों की टीम ने भी अपने हुनर और सामूहिक प्रयासों से दूसरा स्थान हासिल कर पूरे जिले को गर्व महसूस कराया।

यह चैंपियनशिप खेल प्रेमियों और प्रतिभागियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई, जहां राज्य भर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गरियाबंद के पंडुका में आयोजित यह टूर्नामेंट न केवल वुडबॉल के खेल को बढ़ावा देने में सहायक रहा, बल्कि युवाओं को प्रेरित करने का एक मजबूत जरिया भी बना।

प्रदेश के खेल विभाग और आयोजकों ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजेता खिलाड़ियों को खेल प्रेमियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस सफलता के बाद वुडबॉल को लेकर युवाओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह देखा जा रहा है। चैंपियनशिप के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम हैं।

इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गारीयाबंद के कलेक्टर श्री दीपक कुमार अग्रवाल (आईएएस) ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए वुडबॉल जैसे खेल को राज्य स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

चैंपियनशिप का उद्देश्य राज्य के युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करना और वुडबॉल जैसे उभरते खेल को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। आयोजन स्थल पर खेल प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने टूर्नामेंट को और भी खास बना दिया। समारोह का समापन अतिथियों के द्वारा विजेताओं को सम्मानित कर किया गया।

सरकारी गाड़ी की टक्कर से सेनेटरी इंस्पेक्टर चोटिल

बलौदाबाजार। जिले में शासकीय कर्मचारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नशे में धुत्त शासकीय वाहन चालक ने नगर पालिका के सेनेटरी इंस्पेक्टर को अपने वाहन से चोटिल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

सेनेटरी इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल में किनारे खड़ा था और काम करवा रहा था। इसी दौरान शासकीय वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। शासकीय वाहन का चालक नशे में इस तरह धुत्त था कि खड़े भी नहीं हो पा रहा था। किसी तरह लोगों ने बाहर निकाला।

बताया जा रहा है कि उक्त शासकीय वाहन बलौदाबाजार में पदस्थ बड़े अधिकारी की है। शासकीय वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल डैमेज हो गई है। घटना के बाद इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना में घायल मनोज कश्यप सेनेटरी इंस्पेक्टर नगर पालिका बलौदाबाजार ने बताया कि घटना शासकीय महाविद्यालय के पास की है। घटना में मुझे ज्यादा चोट नहीं आई पर मोटरसाइकिल डैमेज हो गई है।

वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल में छात्रा की मौत

■ हार्ट अटैक से जान जाने की आशंका, जांच जारी

रायगढ़। रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगे हुए पटेलपाली गांव में स्थित वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के हास्टल में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के रायगढ़-सारंगढ़ मार्ग के ग्राम पटेलपाली में स्थित वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के हास्टल में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा जो कि शक्ति जिले के मालखैरादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोता की रहने वाली थी।

सोमवार की सुबह अचानक वह बाथरूम गई थी और काफी समय तक नही लौटी तक अन्य छात्रों ने इस मामले की सूचना प्रबंधन को दी। जिसके बाद किसी तरह बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो छात्रा अंदर बेहोशी के हालत में पड़ी मिली। इस घटना के बाद आनन-फानन में छात्रा को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां प्रारंभिक जांच में ही मौके पर मौजूद डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि दो दिनों से छात्रा का तबियत ठीक नही थी और उसे सर्दी खांसी की शिकायत थी। प्रारंभिक जांच के दौरान आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक आने की वजह से संभवत: छात्रा की मौत हुई होगी। फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

हास्टल परिसर में बेहोशी की हालत में मिली छात्रों को उपचार हेतु एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया जहां प्रारंभिक जांच में उसकी मौत हो जाने के बाद विधिवत उसके शव को पीएम के लिये रायगढ़ जिला अस्पताल लाकर पीएम कराना रहता है लेकिन बगैर पीएम के शव को मृतका के गृह ग्राम ले जाना कई संदेहो को जन्म देता है।

इस संबंध में जूटमिल थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने बताया कि छात्रा की तबियत खराब होनें पर उसे उसके परिजन की उपस्थिति में एक निजी अस्पताल ले जाया गया था। जहां छात्रा की मौत हो जाने के बाद परिजन उसे गृह ग्राम कोता ले गए हैं। परिजनों के द्वारा थाने में इस मामले की सूचना नही दी गई थी।

परंतु इस मामले की जानकारी लगते ही मृतका के परिजनों से संपर्क करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। जूटमिल थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने यह भी बताया कि मृतका नाम श्रेया गबेल पिता संजय गबेल 17 साल निवासी मालखरौदा थाना के ग्राम कोता की रहने वाली थी और वैदिक स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ती थी और हास्टल में रहती थी। छात्रा के शव को परिजन मालखरौदा ले गए हैं यहां से एक टीम मौके के लिये रवाना हो गई है उसकी उपस्थिति में पीएम होगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

दंतेवाड़ा जिला अस्पताल से कैदी फरार

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल से शनिवार को एक कैदी फरार हो गया। कैदी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। वहां पुलिस आरक्षक को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके बर्मन ने बताया कि, फरार कैदी का नाम राजू उर्फ भरत नाग है। ये बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लूट के आरोप में इसे अक्टूबर 2024 को दंतेवाड़ा जेल में दाखिल किया गया था। वहीं 2 दिन पहले इसकी अचानक तबियत बिगड़ी थी। जिसके बाद इसे इलाज के लिए पुलिस जवान के साथ जिला अस्पताल भेजा गया। जहां इसने रात के समय पुलिस जवान को चकमा दिया और अस्पताल से भाग निकला। एएसपी ने आगे बताया कि कैदी के अस्पताल से फरार होने की खबर जैसे ही पुलिस अफसरों को मिली तो आस-पास के थानों सहित पड़ोसी जिले की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। आरोपी कैदी अब तक पकड़ा नहीं गया है।

नशे में रायफल लेकर स्कूल पहुंचा प्रधानपाठक

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रधानपाठक शराब के नशे में रायफल लेकर स्कूल पहुंचा और महिला प्राचार्य को धमकाने लगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह मामला प्रतापपुर ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल बरबसपुर का है। बताया जा रहा कि यह घटना 21 नवंबर की है। स्कूल के एक शिक्षक ने प्रधानपाठक का वीडियो बनाया है। वायरल वीडियो में प्रधानपाठक धौंस दिखाते नजर आ रहा है। प्राचार्य के लिखित शिकायत के बाद भी इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

बीजापुर में नक्सलियों ने जियो के टावर में लगाई आग

बीजापुर। जिले के तोयनार थाना क्षेत्र के ग्राम मोरमेड में बीती रात नक्सलियों ने जिओ मोबाईल टावर में आगजनी कर उसे नुकसान पहुंचाया है। आगजनी से टावर में लगे उपकरण जलकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटनास्थल पर पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के नाम का पाम्पलेट मिला है। जिले में संचार सुविधा उपलब्ध कराने गत माह ग्राम मोरमेड के स्कूलपारा के पास यूएसओएफ योजना के तहत जिओ मोबाइल टावर लगाया था। जिसे बीती रात नक्सलियों ने आगजनी कर उसे नुकसान पहुंचाया है। आगजनी से टावर के उपकरण जलकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जियो टीम की तरफ से तोयनार थाना में इस बारे में आवेदन देकर बताया गया है कि रविवार-सोमवार की दरमियानी रात में सादे वेशभूषा में अज्ञात नक्सलियों के द्वारा ग्राम मोरमेड में स्थापित जियो टावर में आगजनी हुई है। नक्सलियों के द्वारा की गई आगजनी से टावर में लगे उपकरण जलकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। है। वही घटनास्थल से नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी द्वारा जारी पाम्पलेट मिला है।

लोगों से भरा ऑटो पलटा, बैगा महिला की मौके पर ही मौत

गौरेला पेंड्रा मरवाही। दशगात्र के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे लोगो से भरा ऑटो पलट जाने से एक बैगा महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। एक बुजुर्ग को भी चोट आई है। मामला जिला गौरेला थाना का है जहां डाहीबहरा सराइपानी गांव के रहने वाले 3 लोग दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने ऑटो से मध्यप्रदेश के सीमावर्ती गांव लहसुना जाने को निकले थे। तभी इन लोगो का ऑटो पलट गया। हादसे में ऑटो में बैठी महिला फुंदरी बाई बैगा की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि अन्य महिला महिला श्याम कली बैगा गंभीर रूप से घायल हो गई। बुजुर्ग फूलचंद बैगा को भी हादसे में चोट आई। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों की मदद से सभी को इलाज के लिए निजी वाहन से जिला अस्पताल में लाया गया जहा जांच के बाद डॉक्टरों ने फुंदरी बाई को मृत घोषित कर दिया। घायलों का इलाज किया जा रहा है।

थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से मजदूर का हाथ कटा

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही में धान की मिसाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से मजदूर का हाथ बाह से उखड़ गया। गम्भीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूर गौरेला के हर्री गांव का रहने वाला है और सीमावर्ती मध्यप्रदेश के कपरिया गांव में थ्रेसर मशीन में काम करने गया हुआ था। जिला चिकित्सालय में सोमवार को एक मजदूर को गम्भीर हालात में भर्ती कराया गया है मजदूर गौरेला के हर्री गांव का रहने वाला तेरस राम मराबी है जो सीमावर्ती मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले के कपरिया गाव में थ्रेसर मशीन से धान मिसाई का काम करने अन्य मजदूरों के साथ गया हुआ था। धान मिसाई के दौरान जब वह धान को मशीन में डाल रहा था तभी तेरस मशीन की चपेट में आ गया और उसका दाहिना हाथ थ्रेसर मशीन के अन्दर जा घुसा वहां मौजूद अन्य मजदूर कुछ समझ पाते जब तक तेरस का दाहिना हाथ बाह से उखड़ गए था। आसपास के लोगों ने तेरस को लेकर जीपीएम के जिला अस्पताल पहुंचे।

स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा क्षेत्र में ही सुविधा नहीं

■ खाट पर हेल्थ सिस्टम, नहीं पहुंच रही एंबुलेंस

मनेन्द्रगढ़। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर स्थिति एक बार फिर उजागर हुई है। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के छिपछिपी गांव की एक घायल महिला को एंबुलेंस सेवा न मिलने के कारण खाट पर रखकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, महिला का पैर बैलों की लड़ाई के दौरान टूट गया था। परिजनों ने 108 एंबुलेंस सेवा पर संपर्क किया। लेकिन उन्हें बताया गया कि एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है। इसके बाद मजबूरन परिजनों ने महिला को खाट पर लिटाकर पिकअप वाहन से मनेंद्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया।

विपक्ष ने इस मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि यह घटना सरकार की विफलता का प्रमाण है। जब मंत्री के क्षेत्र में ऐसी स्थिति है, तो अन्य इलाकों की हालत क्या होगी। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह घटना न केवल प्रशासन की नाकामी को उजागर करती है, बल्कि राज्य की प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं पर भी सवाल खड़े करती है।

मरीज का खाट पर वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भी सोशल मीडिया पर तंज कसा है। गुलाब कमरो ने लिखा है कि दिया तले अंधेरा। जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही एम्बुलेंस की जगह खाट पर मरीज अस्पताल तक लाए जा रहे हो तो प्रदेश के क्या हालात होंगे। यह आसानी से समझा जा सकता है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भिलाई इस्कॉन टेंपल में कीर्तन

भिलाई-दुर्ग। देश भर के इस्कॉन मंदिरों में बांग्लादेश के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कीर्तन किए गए। सेक्टर 6 इस्कॉन मंदिर में इस्कॉन भक्तों ने कीर्तन किया। हरे कृष्ण मूवमेंट भिलाई रायपुर के अध्यक्ष और अक्षय पात्र भिलाई के क्षेत्रीय अध्यक्ष व्योमपद दास ने कहा कि कुछ दिनों से बांग्लादेश से हर रोज खबरें हो रही है कि हिंदू समाज और इस्कॉन के विभिन्न संतों को बंदी बनाया जा रहा है। उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। जिससे इस्कॉन से जुड़े लोग चिंतित है।

व्योमपद दास ने बताया कि हम शांति में आस्था रखने वाले लोग है। राजनीतिक लोग नहीं है।हमारी आध्यात्मिक संस्था है। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि भगवत गीता, भागवत और हमारे वैदिक शास्त्रों के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जाए। भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन किया जाए। हम वहीं तक सीमित है।

व्योमपद दास ने कहा हम अपने घर में अपने समाज में कीर्तन कर रहे हैं, आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो इसमें उन्हें क्या आपत्ति है।

सब का अपनी निजी स्वतंत्र है, उस पर यदि प्रहार किया जाए तो क्या होगा।

व्योमपद दास ने आगे बताया कि हरे कृष्ण मिशन से जुड़े लोग हजारों की संख्या में बांग्लादेश में है। हमारे सनातन धर्म की प्रशस्त और ताकतवर शक्ति बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश में वैष्णव संप्रदाय का बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से उत्पन्न हुआ है। 500 सालों से ये संप्रदाय चल रहा है। उस देश से हमारे संस्था के आचार्य आए हैं।

व्योमपद दास ने बताया कि कुछ कट्टरपंथियों का हल्लाबोल है। वे नहीं चाहते हैं कि हमारी हिंदू संस्था वहां प्रचार करें और एक संगठन के रूप में बनी रहे। संगठन में शक्ति है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो चाहते हैं हिंदू एक हो कर ना रहे वो बंटे लेकिन हम नहीं बंट पा रहे हैं।

हरे कृष्ण मूवमेंट भिलाई रायपुर के अध्यक्ष ने सरकार से मांग है कि बांग्लदेश सरकार को वो सतर्क करें। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हमारी संस्था और हिंदू समाज की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश ना करें। सरकार से मांग है कि हमारे पड़ोसी देशों में हिन्दू अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 साल से बांग्लादेश में सनातनियों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल से मिले सीएम साय, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर हुई चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार

को राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। कैबिनेट की बैठक के ठीक पहले इस मुलाकात से कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री साय ने राज्यपाल से मुलाकात कर नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी समाज को 50 प्रतिशत आरक्षण देने और नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर जानकारी दी। फिलहाल इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले दो दिनों से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लगातार मैराथन बैठक और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने का दौर लगातार जारी है। इससे ये चर्चाएं है कि कैबिनेट की बैठक में इन दो विषयों पर मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के दो पद खाली हैं। इस मुलाकात से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर होने लगी है। बता दें कि राजधानी की चार और रायपुर जिले की सातों सीटें भाजपा के पास हैं, पर यहां से एक भी मंत्री नहीं है।

राज्यपाल रमेन डेका का किया गया प्रकृति परीक्षण

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका का सोमवार

को राजभवन में आयुष विभाग के चिकित्सकों द्वारा प्रकृति परीक्षण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ आयुर्वेद एवं युनानी चिकित्सा पद्धति और नेचरोपैथी काउंसिल रायपुर के रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला, आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. सुनिल दास, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर के प्राचार्य डॉ. जी.आर चतुर्वेदी, डॉ. विनय भारद्वाज और डॉ. ओपी राउत उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान आरंभ किया गया है। यह अभियान संविधान दिवस 26 नवंबर से प्रारंभ है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसम्बर तक चलेगा जिसमे देश व प्रदेश के आयुर्वेद विधा से जुड़े शासकीय एवं निजी शिक्षक, चिकित्सक, छात्र-छात्राओं सहित राज्य में 15 लाख नागरिकों का मोबाइल एप के द्वारा आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप प्रकृति (वात, पित्त, कफ) परीक्षण किया जाएगा।

जीएसटी परिषद की बैठक, छत्तीसगढ़ के वित मंत्री ओपी चौधरी ने रखे अहम सुझाव

रायपुर। राजधानी दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन

में सोमवार को जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वित्त सचिव मुकेश बंसल की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रही। मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं। यह समूह जीएसटी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा। जीएसटी परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी।

हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संगम है : राज्यपाल

रायपुर। राजभवन में सोमवार को असम और नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों,भाषाओं और परंपराओं का संगम है। केन्द्र सरकार के एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते है। इसी कड़ी में आज राजभवन के दरबार हॉल में असम एवं नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर इन राज्यों के लोगों को बधाई दी। राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि इन दो अद्भुत राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर, हमारे लिए उनके समृद्ध इतिहास, अद्भुत संस्कृति और उनकी आशाओं और सपनों के बारे में अधिक जानना महत्वपूर्ण है। उन्होंने असम और नागालैंड राज्य की विशेषताओं को रेखांकित किया। असम राज्य भारत के ईशान कोण में स्थित है और ईशान कोण को भगवान का वास माना जाता है।

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैज ने सरकार पर साधा निशाना

अमित शाह के दौरे पर पूछे ये तीन सवाल

रायपुर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के लिए अध्यादेश लाने की सरकार की कवायद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 'सरकार कंफ्यूज है, फैसला नहीं कर पा रही है। स्पष्ट है सरकार डर रही है। निकाय चुनाव से पहले पीएम आवास के फार्म भरवाने के संबंध में दीपक बैज ने पीएम आवास के लिए स्थाई जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र मांगने को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाये हैं।

गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर पूछे सवाल

गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की मनपसंद एप भी क्या मोदी की गारंटी? लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, क्या गृह मंत्री विजय शर्मा को बर्खास्त करेंगे? बस्तर की जनता के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। नगरनार प्लांट के निजीकरण को लेकर भी पूछा सवाल- निजीकरण सूची से केंद्र ने अब तक नहीं हटाया नगरनार प्लांट का नाम। निजी कंपनियों से सर्वे करा कर क्या संकेत देना चाहती है सरकार?

बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को डराने धमकाने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रम फैलाने में माहिर है। सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब गठित किया गया था। जांच के दायरे में लाने और डराने के उद्देश्य से सरकार साजिश कर रही है। इन बातों को बताने कार्यकर्ताओ ने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की होगी।

यूथ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, आज से 9 तक तहसील ऑफिस का करेगी घेराव

रायपुर। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस मंगलवार से सरकारी सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। युवा कांग्रेस 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक तहसील ऑफिस का घेराव करेगी। वहीं 11 से 17 दिसंबर तक जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में इस संबंध में अहम निर्णय लिए गये। बैठक में प्रदेश प्रभारी शेषनारायण ओझा और प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा मौजूद रहे।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने ऑनलाइन संदेश में आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, आज वह भूल चुकी है। 3100 में धान खरीदी का वादा भाजपा ने किया था पर आज किसानों को एक

साथ पूरी राशि नहीं मिल रही है। लगातार बारदाना की कमी और धान खरीदी में अर्थव्यवस्था से प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में मर्डर,बलात्कार और चोरी जैसी आपराधिक घटनाएं आम बात हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को बड़े एवं छोटे उद्योगों में रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस आने वाले 3 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक पहले छत्तीसगढ़ के प्रत्येक तहसील का घेराव करेगी। उसके बाद सभी जिलों में कलेक्टोरेट का घेराव किया जाएगा। इस घेराव के बाद 17 दिसंबर के बाद एक प्रदेशव्यापी आंदोलन भी होगा। आंदोलन को लेकर यूथ कांग्रेस ने आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है।

इन तीन अहम मुद्दों पर होगा घेराव

1. धान समर्थन मूल्य की वादाखिलाफी,धान खरीदी केंद्र में बारदाना की अव्यवस्था।
2. बेलगाम नशा और लगातार बढ़ते अपराध।
3. छत्तीसगढ़ में बड़े छोटे उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार को लेकर।

जल संसाधन विभाग में नवनियुक्त अभियंताओं के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत

रायपुर। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग ने अक्टूबर 2024 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 81 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति की है। इनमें से 80 अभियंता कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। इन नवनियुक्त अभियंताओं को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित किया गया है। इसी कड़ी में सोमवार 6 दिसंबर यानि आज से रायपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थान में इन अभियंताओं के लिए 5 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका 6 दिसंबर को समापन होगा।

बता दें कि सोमवार को आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उइके सहित प्रमुख अभियंता कार्यालय और रायपुर की संरचनाओं में पदस्थ मुख्य अभियंता उपस्थित रहे। उद्घाटन में भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और राजगीत का प्रसारण हुआ और फिर नोडल अधिकारी ललित रावटे ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। स्वागत के बाद प्रसुन शर्मा, अधीक्षण अभियंता प्रशासन एवं प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उइके ने प्रशिक्षणार्थियों को

मार्गदर्शन संबोधन दिया।

सहायक अभियंताओं को इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में विभाग की कार्य पद्धति के साथ-साथ तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण अवधि में प्रतिदिन 5 सत्र होंगे और प्रत्येक सत्र जो 75 मिनटों का होगा, जिसमें विभाग के पूर्व एवं वर्तमान वरिष्ठ अभियंताओं द्वारा व्याख्यान दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि रायपुर ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से विभाग के अभियंताओं को समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण नियमित रुप से दिया जाता है। नवनियुक्त सहायक अभियंताओं का यह आधारभूत प्रशिक्षण मात्र परिचयात्मक है, बाद में दोबारा विषय से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करके इन सहायक अभियंताओं को विभाग के सभी विषयों का प्रशिक्षण प्रदान दिया जायेगा।

राजधानी के शगुन फार्म्स में आबकारी विभाग ने छापेमारी कर जब्त की प्रीमियम शराब

तो न्यायधानी में हुक्का पार्टी करते नाबालिग समेत 12 लोग गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में आबकारी विभाग और पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने बीती रात रायपुर के वीआईपी रोड स्थित शगुन फार्म हाउस में छापेमारी कर 55 लीटर से अधिक महंगी शराब जब्त की, जबकि बिलासपुर में पुलिस ने एक मकान में दबिश देकर हुक्का पीते हुए एक नाबालिग समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।

अवैध रूप से परोसी जा रही थी शराब

आबकारी विभाग ने शनिवार को रायपुर के वीआईपी रोड स्थित शगुन फार्म हाउस में छापेमारी की और 55 लीटर से ज्यादा महंगी शराब जब्त की। फार्म हाउस में हरियाणा निर्मित प्रीमियम क्वालिटी की शराब

जैसे जगरमिस्टर, ग्लैनलेविट, जॉनी वॉकर गोल्ड लेबल, रोकु जीन, ग्रे गूज वोदका, सिल्वर पैटरॉन टकीला, जैकब क्रीक, सुला और कोरोना जैसी महंगी शराब की बोतलें मिलीं। ये शराब हरियाणा से तस्करी कर मंगाई गई थी और छत्तीसगढ़ में इनकी कीमत प्रति बोतल 5000 रुपये से ज्यादा है, जबकि हरियाणा में ये शराब 1200 से 2000 रुपये के बीच मिलती है।

यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त आर. संगीता और कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर आबकारी उपायुक्त रामकृष्ण मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई। विभाग की टीम ने फार्म हाउस में छापे के दौरान शराब की अवैध बिक्री की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक, फार्म हाउस में शहर के बड़े कारोबारियों की वीकेंड पार्टी चल रही थी और शराब परोसने के लिए जरूरी लायसेंस नहीं लिया गया था। इसलिए ये कार्रवाई की गई ।

वहीं, बिलासपुर के रिंग रोड 2 स्थित एक मकान में पुलिस ने दबिश दी और हुक्का पीते हुए एक नाबालिग समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी रजनेश सिंह को सूचना मिली थी कि पल्लव भवन के पास एक मकान में हुक्का बार चल रहा है। इसके बाद एसीसीयू टीम ने देर रात मकान में छापेमारी की और कमरे में शतरंज खेलते और हुक्का पीते हुए 12 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने मौके से हुक्का, विभिन्न प्रकार के तम्बाकू और 18,500 रुपये नकद जब्त किए।

सिविल लाइन पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ सिगरेट और तम्बाकू अधिनियम, 2003 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में प्रीस कश्यप, शौर्य कश्यप, शुभम मखीजा, अरनव मिश्रा, राज कश्यप, दक्ष कश्यप, विनीत ऐलानी समेत अन्य लोग शामिल हैं।

श्री नारायणा हॉस्पिटल में डिजिटल हेल्थ मास्टरक्लास का हुआ आयोजन

■ एएचपीआई के सहयोग से बना कोर्स

रायपुर। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) और श्री नारायणा हॉस्पिटल, देवेंद्र नगर, रायपुर द्वारा कोयटा फाउंडेशन के सहयोग से राज्य स्तरीय डिजिटल हेल्थ मास्टर क्लास का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में करकीनोस हैल्थकेयर के उपाध्यक्ष आरकेपी चित्तूर रेड्डी ने विस्तार से स्वास्थ्य क्षेत्र में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड की उपयोगिता के बारे में विस्तार से चर्चा की है।

एएचपीआई के डायरेक्टर डॉ। सुनील खेतरपाल, कोयटा फाउंडेशन से डॉ। अनुजा सनखे, श्री नारायणा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ। सुनील खेमका, एएचपीआई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता, महासचिव

अतुल सिंघानिया सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के कई ख्याति प्राप्त लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

एएचपीआई के डायरेक्टर डॉ। सुनील खेतरपाल ने कार्यशाला में उपस्थित सभी डेलिगेट्स का स्वागत करते हुए उन्हें इस कार्यशाला के महत्त्व के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने श्री नारायणा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर को स्वयं वालंटियर कर इस वर्कशॉप का आयोजन का प्रस्ताव देने के लिए डॉ। खेमका का आभार व्यक्त किया।

एएचपीआई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि एएचपीआई देश के स्वास्थ्य प्रदाता संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें 27,000 से भी ज्यादा सदस्य अस्पताल हैं। एएचपीआई केंद और राज्य सरकारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कोयटा फाउंडेशन की डॉ. अनुजा सनखे ने बताया कि एएचपीआई के सहयोग से इस डिजिटल हेल्थ मास्टर क्लास का कोर्स कंटेंट बनाया गया है। जिससे छोटे और मध्यम अस्पतालों में डिजिटल तकनीक अपनाई जा सके। कोयटा फाउंडेशन के अध्यक्ष रिज़वान कोयटा हैं जो अस्पतालों की गुणवत्ता निर्धारित करने वाली संस्था ह्वक्का के चैयरमैन भी हैं।

श्री नारायणा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और एएचपीआई छत्तीसगढ़ की एडवाइजरी समिति के सदस्य डॉ। सुनील खेमका ने कहा कि यह वर्कशॉप मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी आधारित सर्विस डिलीवरी का है।

एएचपीआई के महासचिव अतुल सिंघानिया ने मंच का संचालन और आभार प्रदर्शन किया। अतुल सिंघानिया ने बताया कि इस वर्कशॉप में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के 57 अस्पतालों के 100 से ज्यादा डेलिगेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया जिसमें छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश के लोग भी शामिल थे।

विष्णु के सुशासन में तेजी से हो रहे विकास कार्य : साव

■ पीसीसी चीफ बैज ने कहा- हर मामले में सरकार विफल

रायपुर। साय सरकार के एक साल पूरे होने पर सरकार विजय पर्व मनाने जा रही है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, एक साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। मोदी की गारंटी की दिशा में कदम उठाए गए। असंभव सा काम भी विष्णु के सुशासन में हुए हैं। गांव और शहर के अवरुद्ध हुए विकास को फिर गति मिली है। हमने बनाया था और हम ही संवारने का काम कर रहे हैं। 13 दिसंबर को एक साल पूरा होने जा रहा है। इधर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए विजय पर्व को शर्मनाक बताया है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले जल रहे हैं। एक साल में छत्तीसगढ़ लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या का गढ़ बन चुका है। 32 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेकर सरकार ने राज्य को डुबा दिया है। जनता पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, हर कोई एक दूसरे को मार रहे। हर मामले में सरकार विफल हुई है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है और ये विजय पर्व माना रहे। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

प्रधानमंत्री ई बस सेवा से सफर होगा सुहाना, छत्तीसगढ़ के चार शहरों का चयन

■ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में ई बसें दौड़ेंगी

रायपुर। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर भारत सरकार प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 और कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा को नोडल एजेंसी और जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।इन बड़े शहरों के नागरिकों को जल्द ही ईको फ्रेंडली बसों में सफर करने का सुखद अनुभव मिलने वाला है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुताबिक ई-बस सेवा शुरु होने से छत्तीसगढ़ के शहरों

में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।

सुडा ने रायपुर में बस सेवा शुरु करने के लिए बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 14 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इसमें आठ करोड़ 60 लाख रुपए का केन्द्रांश और पांच करोड़ 73 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। सुडा ने बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 12 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

दुर्ग-भिलाई में ई-बसों के बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को छह करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सुडा ने जारी की है। इसमें चार करोड़ चार लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 69 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। वहां बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 करोड़ दो लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

बिलासपुर में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलासपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को आठ करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें पांच करोड़ दो लाख रुपए का केन्द्रांश और तीन करोड़ 35 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तीन करोड़ आठ लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

इसी तरह कोरबा में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोरबा अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को सात करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें चार करोड़ 31 लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 88 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां तीन करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख और पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता है। इसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसों, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसों, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसों तथा कोरबा को 20 मीडियम एवं 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

लगातार चुनाव क्यों जीतती रहती है भाजपा

राम माधव

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत अप्रत्याशित नहीं थी। हालांकि, भाजपा ने 90 प्रतिशत से अधिक सीटों पर जीत हासिल की और उसके सहयोगियों ने भी शानदार जनादेश हासिल किया। भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। पंचायतों से लेकर संसद तक, यह हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाती है। इसमें अपनी गलतियों से सीखने और जल्दी से जल्दी सुधार करने की जबरदस्त क्षमता है। अंत में, यह कुछ जीत सकती है और कुछ हार सकती है। लेकिन जब अगला चुनाव आता है, तो पार्टी पूरी ताकत से तैयार रहती है। भारत में किसी अन्य पार्टी ने चुनावों के दौरान ऐसा जादू नहीं दिखाया है। कहा जाता है कि सफलता के कई पिता होते हैं, असफलता अनाथ होती है। महाराष्ट्र इसका अपवाद नहीं है। हालांकि, भाजपा नेतृत्व हमेशा यह समझता है कि चुनाव में जीत या हार किसी एक कारक के कारण नहीं हो सकती। कुछ निश्चित ताकतें होती हैं, लेकिन हर चुनाव में कुछ चर होते हैं। 7 दशकों से ज्यादा समय तक चली अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा में, पहले भारतीय जनसंघ (बी.जे.एस.) के रूप में और बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में, पार्टी ने अपनी चुनावी मशीन को मजबूत किया है। जहां तक स्थिरांकों का सवाल है, यह नेता, कैडर और परिवार की तिकड़ी पर निर्भर करता है। अतीत में अटल बिहारी वाजपेयी व लाल कृष्ण अडवानी और अब नरेंद्र मोदी ने पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पी.एम. मोदी ऐसा नेतृत्व प्रदान करते हैं जो देश के राजनीतिक इतिहास में दुर्लभ है। वे सत्ता विरोधी लहर के बारे में पारंपरिक राजनीतिक ज्ञान को चुनौती देते हैं। यही कारण है कि पार्टी बिना किसी खेद के अपनी चुनावी जीत का श्रेय उस बढ़ती हुई व्यापक अपील को देती है जो प्रधानमंत्री को सत्ता में 10 साल से ज्यादा समय के बाद भी हासिल है। प्रधानमंत्री पद के साथ-साथ भाजपा के लिए 2 अन्य महत्वपूर्ण स्थिरांक हैं-इसकी सुव्यवस्थित संगठनात्मक मशीनरी और संघ परिवार से मिलने वाला अनौपचारिक महत्वपूर्ण समर्थन। महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर भी, उनका योगदान बहुत बड़ा था। इन स्थिरांकों से परे ऐसे चर हैं जिन पर पार्टी ने दशकों के अनुभव से महारत हासिल की है। एक विचारधारा से प्रेरित पार्टी के रूप में शुरू हुई भारतीय जनसंघ ने 1967 में अपना पहला लिटमस टैस्ट तब देखा जब उसे समाजवादियों और कम्युनिस्टों जैसे वैचारिक कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के साथ हाथ मिलाकर 7 राज्यों में संयुक्त विधायक दल (एस.वी.डी.) की सरकार बनाने या अपने वैचारिक शुद्धतावाद को जारी रखने और बाहर बैठने की दुविधा का सामना करना पड़ा। पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय, जो मूल रूप से आर.एस.एस. के नेता थे, ने गठबंधन की राजनीति के महत्व को समझा और एस.वी.डी. गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय जिससे उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। अपनी आत्मकथा में, वरिष्ठ नेता अडवानी, जो उपाध्याय के लंबे समय से सहयोगी रहे, दिसम्बर 1967 में कालीकट पार्टी सम्मेलन में इस मुद्दे पर हुई एक जीवंत चर्चा को याद करते हैं। पंजाब में बसे तमिल विश्वनाथन ने उपाध्याय के फैसले की आलोचना करते हुए एक शक्तिशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जनसंघ को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कम्युनिस्टों के साथ मिलकर हम उन्हें बदल पाएंगे। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक ज्वलंत रूपक का उपयोग किया 'खरबूजा चाकू पर गिरे, या चाकू खरबूजे पर; कटेगा तो खरबूजा ही।' उपाध्याय को कार्यकर्त्ताओं को एस.वी.डी. प्रयोग की प्रभावशीलता के बारे में समझाने के लिए बुद्धि और व्यावहारिक राजनीति के संयोजन का उपयोग करना पड़ा। हम, जनसंघ में, निश्चित रूप से कम्युनिस्टों की रणनीति और राजनीतिक संस्कृति से सहमत नहीं हैं। भाजपा के जन्म के बाद, गठबंधन की राजनीति 1989, 1996, 1998 और 1999 में सफलतापूर्वक आगे बढ़ी। संक्षेप में, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर नरेंद्र मोदी तक और एस.वी.डी. से लेकर महायुति तक यही लचीलापन और व्यावहारिकता है जिसने पार्टी को आगे बढ़ाया और जीता, न कि ई.वी.एम. में हेरफेर जैसा कि कुछ लोग शिकायत करना चाहते हैं।

क्या कांग्रेस में सचमुच कोई आमूल बदलाव होगा?

अजय बोकिल

पहले हरियाणा व अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों परिणामो से हैरान और उद्वेलित कांग्रेस पार्टी अगर सचमुच गंभीर आत्मनिरीक्षण और संगठनात्मक ढांचे में आमूल सुधार करने जा रही है तो इससे अच्छी कोई बात पार्टी और देश के लिए हो नहीं सकती। महाराष्ट्र व हरियाणा में इस बार सत्ता में लौटने का सपना देख रही कांग्रेस की दयनीय पराजय के बाद दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ खरी खरी बातें कहीं। लेकिन ये तमाम बातें व्यावहारिक अंजाम तक भी पहुंचेंगी, यह खरगे भी नहीं जानते।

खरगे ने अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमे चुनाव परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा, माहौल पक्ष में मतलब जीत की गारंटी नहीं है। इस पर बैठक में मौजूद पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने खरगे से कहा कि वो इस मामले में सख्त एक्शन लें।

यहीं सबसे बड़ा पेंच है कि क्या खरगे सचमुच कोई कठोर एक्शन लेने की स्थिति में हैं? क्या उनके पास व्यवहार में ऐसे अधिकार हैं? वो अगर एक्शन लेंगे भी तो किनके खिलाफ लेंगे? दूसरे, बैठक में पार्टी को कसने को जो नेक सुझाव खरगे ने दिए, उन पर पहले ही अमल करने से उन्हें किसने रोका था? यह आत्मज्ञान उन्हें अभी क्यों हुआ? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तो वो दो साल से हैं।

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की मूल समस्या ही ये है कि उसका सिर से पैर तक संगठनात्मक ढांचा चरमराया हुआ है। खासकर 2014 के बाद तो उसकी स्थिति और भी बदतर होती गई है। हर चुनावी हार के बाद यह बात उठती है कि पार्टी संगठन में सुधार जरूरी है। लेकिन हकीकत में सुधार के लिए कुछ नहीं होता है। होता भी है तो दिखावे के लिए। उसमें भी किसी राज्य, कुछ लोकसभा सीटों या स्थानीय निकायों के चुनावों में मिली क्षणिक सफलताएं पार्टी की आंतरिक कलह और अंतर्विरोधों को फिर कालीन के नीचे सरका देती हैं।

इस बार भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में

आत्मालोचन की कोशिशें हुईं। कुछ सच्चाई बयान भी की गई। लेकिन इसके परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर कुछ ठोस होगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। क्योंकि समय पर निर्णय न होना, अवसर चूक जाने के बाद फैसले होना, फैसलों में भी जमीनी हकीकत और जरूरत को ध्यान में रखने की जगह व्यक्तियो के पूर्वाग्रहों का हावी होना, अंतर्कलह पर काबू न होना, गुटीय संतुलन में वक्त जाया होना, शीर्ष नेताओं का चंद चेहरों से घिरा होना, परिणामों के बाद की संभावित स्थिति के मद्देनजर अपना वर्चस्व में कायम रखने की जोड़ तोड़ करना, हर बात में हाई कमान के भरोसे रहना, जमीन पर काम करने की जगह आला कमान का कृपापात्र बनने की होड़ कायम रहना, जमीनी कार्यकर्ता की केवल चुनाव के समय पूछ परख होना, चुनाव जीतने , काल परिस्थिति और स्थानीय जरूरत के हिसाब रणनीति बनाने और तदनुसार मुद्दे उठा सकने में विफल रहना, स्पष्ट वैचारिक सोच न होना, संगठन को सतत निरंतर राजनीतिक काम में व्यस्त न रख पाना, सचबयानी करने वाले चंद चेहरो को खारिज करना, कभी क्षेत्रीय दलों की तरह व्यवहार करना तो कभी खुद को राष्ट्रीय पार्टी की तरह पेश करना ऐसी पुरानी और गंभीर बीमारियां हैं, जिनका इलाज पार्टी आज तक नहीं खोज पाई है।

बहरहाल सीडबल्यूसी की बैठक में खडगे ने कुछ अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि खड़गे ने कहा कि राज्य चुनावों में उम्मीद से कम प्रदर्शन हमारे लिए चुनौती है। पार्टी नेताओं में एकता की कमी, एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चुनावों में हमें नुकसान पहुंचा रही है, इस पर सख्त अनुशासन की जरूरत है। पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर से लेकर एआईसीसी तक बदलाव लाने होंगे। खड़गे ने यह भी कहा कि चुनाव का माहौल हमारे पक्ष में होने से जीत की गारंटी नहीं मिलती।

समयबद्ध रणनीति बनाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। विधानसभा चुनावों के लिए एक साल पहले से तैयारी करनी होगी, मतदाता सूचियों की जांच करनी होगी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता में आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश भर में लोगों के एजेंडे को लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के अच्छे नतीजों के बाद विधानसभा चुनाव नतीजों ने हमें झकझोर दिया, हमें कड़े कदम उठाने होंगे।

जहां तक पार्टी में सुधार की बात है तो यह मुद्दा कई बार उठा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के कारणों का पता लगाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी की अगुवाई में कमेटी बनी थी। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में हार के कई कारण बताए। वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। लेकिन बताया जाता है कि रिपोर्ट में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में एक शब्द नहीं कहा या ऐसा कर सकने का साहस उसमें नहीं था। जबकि पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में हारी थी।

उसी साल हुए कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस की हार के बाद 2016 में पार्टी के तत्कालीन महासचिव दिग्विजयसिंह ने पार्टी में मेजर सर्जरी की जरूरत बताई थी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पार्टी का ढर्रा जैसा चल रहा था, चलता रहा। लेकिन 2024 में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया तो क्रेडिट राहुल गांधी को दी गई, जबकि वो पार्टी अध्यक्ष नहीं हैं। ऐसे में खड़गे कितनी दमदारी से एक्शन ले पाएंगे, यह समझा जा सकता है।

बैठक में दूसरा अहम मुद्दा ईवीएम का रहा। हर हार के बाद कांग्रेस का विश्वास इस मशीन से उठने लगता है तो जीतने पर वह ईवीएम के नतीजों को वास्तविक जनादेश बताने लगती है। खरगे ने भी कहा कि ईवीएम ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है, चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन ईवीएम को लेकर यह प्रश्नचिन्ह केवल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर ही है। इसमें पिछले दिनो हुए हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना अथवा कर्नाटक राज्य के विस चुनाव शामिल नहीं हैं और न ही लोकसभा में महाराष्ट्र व यूपी आदि राज्यों के नतीजों पर सवालिया निशान है।

यह भी खास बात है कि ईवीएम की बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पैरवी कर रही कांग्रेस उसके द्वारा शासित राज्यों में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव भी बैलेट पेपर से नहीं कराती। मसलन हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार वजूद में आने के बाद शिमला नगर निगम के चुनाव ईवीएम से हुए। उसमें कांग्रेस जीती तो किसी को ईवीएम में कोई खोट नजर नहीं आई। अगर पार्टी का ईवीएम से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है तो उसके द्वारा शासित राज्यों के राज्य चुनाव आयोगो को बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या अड़चन है? अब पार्टी महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर जन आंदोलन करने जा रही है। इसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी साथ लिया जाएगा। आंदोलन केवल महाराष्ट्र में इसलिए है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटक, जम्मू काश्मीर आदि राज्यों की सरकारों को ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है।

इस आंदोलन को जनता को कितना समर्थन मिलेगा, यह देखने की बात है। क्योंकि राजनीतिक अपने चश्मों से हिसाब से कुछ भी देखें, आम मतदाता को पता होता है कि उसने किसको वोट दिया है और क्यों दिया है। वैसे ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस में एकमत नहीं है। पी. चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेता मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करना संभव नहीं है। यह बात इसलिए भी सही लगती है कि चुनाव अब केवल चुनाव सभाओं में लुभावनी या लच्छेदार बातों से नहीं जीते जाते, बूथ मैनेजमेंट और अपने वोट हर हाल में डलवा सकने वाली पार्टी के मशीनरी के जरिए जीते जाते हैं। अगर माहौल पार्टी के पक्ष में हो तो भी यदि उसी अनुपात में वोट नहीं गिरे तो इस खाम खयाली का कोई मतलब नहीं है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

गतांक से आगे...

हम उपर्युक्त प्रमाणों के सम्बन्ध में स्वयं कुछ न कहते हुये विज्ञ पाठकों से ही पूछना चाहते हैं कि आर्यसमाज की प्रत्येक वस्तु को वेद में दिखाओ इस अनुचित माँग का इससे बढ़कर और क्या उत्तर हो सकता है? जिस समाज का प्रवर्तक किसी पादरी के यह पूछने पर कि वेदों में तोप का जिक्र नहीं मिलता, तो झट से दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा..

यथेन्द्रात्रु: स्वरतोप राधात पढ़कर कानों को फाड़ देने वाला दुष्ट शब्द जिसका होता है, ऐसी भयङ्कर तोप से राजा को अपने शत्रु भार डालने चाहिएँ - ऐसा अर्थ कर सकता है तथा अध्यात्मज्ञान के भण्डार वेदों में तार, तोप, ट्राम तथा बिजली का तुच्छतर भौतिक-विधान निकालने के लिए समस्त ऋषि-मुनियों एवं वेद-भाष्यकारों को अंगूठा दिखा सकता है, उसे और उसके समाज को उनकी ही आविष्कृत शैली से मूक कर देना सर्वथा न्याय है।

आशा है, विज्ञ पाठक हमारे भाव को समझकर उपर्युक्त प्रमाणों का मनन करेंगे। मन्त्र ब्राह्मण दोनों हैं वेद, न इन दोनों में किंचित् भेद। ग्रन्थ अष्टादश नाम पुराण, यही चौथा अध्याय बखान ।।

अष्टादशपुराणानां, कर्ता सत्त्यवतीसुत: ।
निरस्य सर्वानाक्षेपानित्येतदिह साध्यते ।।

यद्यपि बिगत अध्यायों में मुक्ति-प्रमाण-पुरस्सर यह सिद्ध किया जा चुका है कि पुराणों के वक्ता, मन्त्रद्रष्टा ऋषि लोग हैं और उन्हें गुरु-परम्परा से प्राप्त करने वाले वही प्राचीनतम वेदाध्ययन-परायण मुनिजन हैं तथा इनको इस प्रकार ग्रन्थरूप में निबद्ध करने वाले भी वेदसंहिताओं के संकलयिता पूज्य कृष्णद्वैपायन जी महाराज ही हैं। इस तरह वक्तृत्व और कर्तृत्व-सामान्यता के कारण पुराण-ग्रन्थ भी वेदों के बाद प्रमाण-कोटि में सन्निविष्ट हैं, परन्तु कुछ लोग यथा तथा पुराणेषु छिद्रान्वेषणम् की कुप्रवृत्ति से प्रेरित होकर वर्तमान पुराणों के **(क्रमश:)**

एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने परिवार नहीं बल्कि राष्ट्र हित को सर्वोच्च महत्व दिया

सुधांशु

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म तीन दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा बिहार के छपरा जिला स्कूल गए से हुई थीं। अपने शैक्षिक जीवन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला लेकर कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। पढ़ाई-लिखाई में डॉ प्रसाद इतने होनहार थे कि परीक्षक ने उनकी परीक्षा की कॉपी को जांचते हुए लिखा था कि- The Examinee is better than

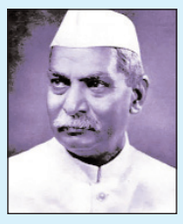

Examiner। डॉ. प्रसाद बहुभाषी होने के साथ-साथ उनकी हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली एवं फारसी भाषा में अच्छी पकड़ थी।

वहीं, 13 साल की उम्र में ही डॉ प्रसाद का विवाह राजवंशीदेवी से हो गया था। जिसके बाद उन्होंने अपने शैक्षिक जीवन को आगे बढ़ाया और बाद में वकालत करते हुए अपने करियर की शुरूआत की। इसके साथ ही उन्होंने भारत को आजाद कराने की कसम खाई और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लिया। सन् 1931 को राजेंद्र प्रसाद को ब्रिटिश प्रशासन ने नमक सत्याग्रह और सन् 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कारावास में डाल दिया था।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बाद वे स्वतंत्र भारत पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गये उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक रहा। डॉ. प्रसाद ने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखलअंदाजी का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपना काम स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से किया। हिंदू अधिनियम पारित करते समय राजेंद्र प्रसाद जी ने काफी कड़ा रुख अपनाया था। साल 1962 में राष्ट्रपति पद से हट जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया था। डॉ प्रसाद के जीवनकाल का एक दिलचस्प किस्सा ये भी रहा कि 25 जनवरी 1950 के दिन उनकी बहन भगवती देवी का निधन हुआ और अगले ही दिन देश का यानी आजाद भारत का संविधान लागू होने जा रहा था ऐसे में भला वो कैसे अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाते। इन परिस्थितियों को देखते हुए डॉ प्रसाद ने संविधान की स्थापना की रस्म पूरी होने के बाद ही दाह संस्कार में भाग लिया।

देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला। इसके साथ ही डॉ राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रा भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वर्ष 1957 में वह दोबारा राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए। बता दें कि डॉ राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, जो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनें। बता दें कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपना आखिरी समय पटना के एक आश्रम में बिताया था। बीमारी के चलते 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया।

बांग्लादेश : इस्कॉन संत की गिरफ्तारी बहाना है...

सुबीर भौमिक

नोबेलजयी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वही कार्ड खेला है, जो मुल्क के अलोकप्रिय नेता अतीत में भी खेलते रहे हैं, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्ड। इस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जमानत देने से भी इन्कार कर दिया गया। दरअसल, यह सब वहां रहने वाले हिंदुओं को भड़काने के लिए किया गया, जो शेख हसीना सरकार के हटने के बाद से ही बढ़ते अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। इस तरह का अत्याचार बांग्लादेश में पहले भी हुआ है, लेकिन हिंदुओं ने कभी इस तरह का व्यापक प्रदर्शन नहीं किया, जैसा कि इस बार अगस्त से वे कर रहे हैं।

इस्कॉन संत ने मुल्क के हिंदुओं को संगठित एवं एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए यूनुस की मंडली को पता था कि संत चिन्मय की गिरफ्तारी से नाराज हिंदू जमकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। एक ऐसे मुल्क में, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और कुल आबादी में जिनकी 93 फीसदी की हिस्सेदारी है, वहां हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ प्रतिक्रिया होने की पूरी आशंका है, क्योंकि इस समय छात्र-युवा समूहों के मुखौटे के पीछे इस्लामी कट्टरपंथियों का बोलबाला है। इसलिए जब सरकार जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने या कानून-व्यवस्था में गिरावट को नियंत्रित करने में असमर्थ हो, तो अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने से बेहतर उपाय और क्या हो सकता है!

इस्कॉन संत की गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन और चटगांव में एक मुस्लिम वकील की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या ने यूनुस सरकार के तात्कालिक उद्देश्यों को पूरा कर दिया। अचानक पूरे मुल्क का ध्यान हिंदू विरोध प्रदर्शनों पर चला

गया और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणियों ने लोगों का ध्यान अर्थव्यवस्था पर से हटा दिया, जो निरंतर चरमरा रही है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालती याचिकाएं और चिन्मय प्रभु पर मुकदमा चलाने की सरकार की योजनाएं अन्य खबरों को सुर्खियों से दूर रखने में मदद करेंगी।

सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ने के साथ ही मुल्क में पहले से कम होती धर्मनिरपेक्ष राजनीति और बंगाली राष्ट्रवादी ताकतों को हाशिये पर धकेल देगी और इस तरह इस्लामी पार्टियों को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। इन पार्टियों ने पहले ही यूनुस सरकार को मुल्क के भाषायी-धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को कम करके मुक्ति संग्राम की विरासत को कमजोर करने के लिए प्रेरित किया है। मुक्ति संग्राम संग्रहालय में भी तोड़फोड़ के साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया है।

यूनुस को घेरने और पश्चिम को नियंत्रित करने के लिए उनका इस्तेमाल करने वाले इन कट्टरपंथी तत्वों ने भारतीय नाराजगी का भी हिसाब लगाया। वे जानते हैं कि चिन्मय की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत की सत्तारूढ़ सरकार तीखी प्रतिक्रिया करेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा चिन्मय की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद यूनुस सरकार ने इसलिए भी की थी, क्योंकि मोदी सरकार वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के उत्पीड़न के मुद्दे को यूनुस प्रशासन के समक्ष जोरदार तरीके से उठाती रही है। विदेश मंत्रालय के बयान पर यूनुस सरकार की ओर से की गई कड़ी प्रतिक्रिया भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए एक सुनियोजित प्रयास की ओर इशारा करती है।

ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि भारत शेख हसीना और उनके कई करीबी सहयोगियों को शरण दे रहा है, जिनमें कुछ पूर्व मंत्री और अवामी लीग पार्टी के नेता शामिल हैं। जब यूनुस या उनकी मंडली में कोई भी अल्पसंख्यक विरोध प्रदर्शनों का उपयोग करके %निहित स्वार्थों% की बात करता है, तो उनका स्पष्ट मतलब अवामी लीग से होता है। पिछले तीन महीनों में, अवामी लीग को क्रूर प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और कम विश्वसनीय आरोपों पर ढेरों मामलों के बावजूद कुछ वरिष्ठ नेताओं ने जमीनी स्तर पर समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश की, जिसे हसीना सरकार के खिलाफ जन-आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र-युवा समूहों द्वारा क्रूरता पूर्वक विफल कर दिया गया।

इन समूहों को इस्लामी दलों और उनके कट्टरपंथी कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। पुलिस अक्सर मूक दर्शक बनकर खड़ी रही है। सेना ने भी ज्यादातर मौकों पर ऐसा ही किया है। यूनुस और उनके साथियों को संदेह है कि अवामी लीग के कार्यकर्ता अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मुद्दे पर उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए हिंदुओं की रैलियों में शामिल हो सकते हैं। जब इसे अंतरिम प्रशासन द्वारा इस्लामी कट्टरपंथियों को विशेष सहायता देने के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसमें अंदरुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी जैसे दोषी आतंकवादियों की रिहाई शामिल है, तो यूनुस शासन का असली चेहरा सामने आ जाता है।

यूनुस भारतीय प्रतिक्रिया को भले ही निराधार बताकर खारिज कर दें, लेकिन जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर बोलते हैं, तो यूनुस को उन्हें गंभीरता से लेना ही पड़ता है, क्योंकि उनका शासन, केवल पश्चिमी, विशेषकर अमेरिकी समर्थन से ही जीवित रह सकता है। असल में यूनुस सरकार ब्रिटिश सर्वदलीय संसदीय मंच की एक रिपोर्ट से परेशान है, जिसमें नई अंतरिम सरकार की प्रभावकारिता पर सवाल उठाए गए हैं। उक्त रिपोर्ट में कहा गया है, कानून को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संस्कृति को समाप्त करने और मानवाधिकारों व कानून के शासन को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसमें विफलता मोहम्मद यूनुस के नए अंतरिम शासन पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि हमें सबूत मिले हैं कि अवामी लीग के पूर्व मंत्रियों पर हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं।

जाहिर है कि, अगर यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और लोकतंत्र की बहाली के मुद्दे से निपटने में विफल रहती है, तो संदेह का घेरा उस पर और कसेगा।

आज का इतिहास

1910 फ्रांसीसी भौतिकशास्त्री जॉर्जेज क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियोन लैम्प का पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शन किया।
1910 आधुनिक नियॉन लाइटिंग को पहली बार पेरिस मोटर शो में इंस्टॉलेशन जार्ज क्लाउड के बाद सार्वजनिक रूप से देखा गया था।
1915 भूटान और अरुणाचल प्रदेश में 6.5 तीव्रता वाले भूकंप से 170 लोगों की जान गयी और कई घर नष्ट हो गए।
1927 फिलिप पर पैंट डालते हुए, कॉमेडी जोड़ी लॉरेल और हार्डी की विशेषता वाली पहली आधिकारिक फिल्म रिलीज़ हुई।
1948 पूर्वी चीन सागर में चीनी शरणार्थी जहाज को ले जा रहे जहाज कियांग्या में विस्फोट होने से 1,100 लोगों की मौत हुई।
1951 लेबनान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।
1959 सिंगापुर के वर्तमान ध्वज को अपनाया गया था, छह महीने बाद सिंगिंगापुर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्व-शासन बन गया।
1960 म्यूजिकल कैमलॉट (जूली एंड्रयूज और रिचर्ड बर्टनप्रीक्टर्ड), जो जॉन एफ कैनेडी की प्रेजिडेंसी के साथ संबद्ध हो जाएगा, ब्रॉडवे पर खोला गया।
1967 कार्डियक सर्जन क्रिस्टियान बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ग्रोट शुतुरहॉट्स में लुई वाशकेन्स्की पर पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया।
1967 इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो नजरबंद किये गए।
1976 आयरलैंड के 6 वें राष्ट्रपति के रूप में पैट्रिक हिलेरी को निर्विरोध चुना गया।
1979 दो दिवसीय जनमत संग्रह के परिणामों के अनुसार, इस्लामी गणतंत्र ईरान के वर्तमान संविधान को अपनाया गया था।
1992 अत्यधिक मौसम की स्थिति के दौरान, तेल टैंकर एजियन सियरन ने गैलिसिया, स्पेन के तट पर घेर लिया, जिसमें 67,000 टन हल्का कच्चा तेल फैला था। 2008
1997 121 देशों के प्रतिनिधियों ने ओटावा संधि पर हस्ताक्षर करके एंटी-कर्मियों भूमि खदानों के उपयोग पर हस्ताक्षर किए।
1999 मार्सैंड के वातावरण के गायब होने से पहले नासा ने मार्स पोलर लैंडर (चित्रकार के चित्र) के साथ संपर्क खो दिया था। 2009
2005 पाकिस्तान के सूचना मंत्री का दावा है कि पाकिस्तानी सेवाओं ने अफगानिस्तान की सीमा पर लड़ाई में अल-कायदा के ऑपरेशनल कमांडर अबू हमजा राबिया की हत्या कर दी है। 2009
2006 मार्क रावलोमनाना, मौजूदा नेता को मेडागास्कर चुनावों में मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। 2011

बदलाव की सिर्फ बात करती है कांग्रेस

राशिद किदवई

वर्ष 1849 में फ्रांसीसी लेखक जीन-बैप्टिस्ट अल्फोंस कार ने लिखा था, 'जितना अधिक बदलाव किया जाता है, उतनी ही अधिक यथास्थिति बनी रहती है'। आज के हालात में यह कथन कांग्रेस पर पूरी शिद्दत के साथ लागू होता है- बदलाव की जितनी अधिक बातें, यथास्थिति के प्रति उतना ही अधिक दुराग्रह। और यही यथास्थितिवाद कांग्रेस की मौजूदा समस्याओं की जड़ बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय के कारणों पर चर्चा करने के लिए 29 नवंबर को आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में एक बार फिर से उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जो पार्टी हर चुनाव में पराजय के बाद दोहराती आयी है। हालांकि इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। एक, संगठन में फेरबदल का और दूसरा, जवाबदेही का। जवाबदेही की बात राहुल गांधी भी लगातार करते आये हैं। जब वह पार्टी अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने जवाबदेही का मसला उठाया था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने स्वयं तो अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, पर बाकी की जवाबदेही कभी तय नहीं की जा सकी।

खरगे ने यह कहकर, कि राज्यों के चुनाव में हम जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाते हैं, वे इतने प्रभावी नहीं होते, एक तरह से राहुल गांधी के आस-पास की उस मंडली पर सवाल उठाया है, जो उन्हें परामर्श देती आयी है। हालांकि राहुल गांधी के प्रति खरगे के मन में असीम सम्मान है, लेकिन उन्होंने उन्हें यह संकेत देने में कोताही नहीं बरती कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और खासकर रणनीतिकारों की जवाबदेही तय करने का वक्त आ चुका है। इन रणनीतिकारों में सबसे प्रमुख हैं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल। पर एक के बाद दूसरे चुनावों में पराजय के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व उन्हें हटा नहीं पा रहा। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जयराम रमेश, पवन खेड़ा तथा सुप्रिया श्रीनेत के बीच तालमेल का अभाव भी बार-बार नजर आता है। पर इसको लेकर भी कांग्रेस नेतृत्व कुछ नहीं कर पा रहा। कांग्रेस की समस्या यह है कि चुनावी हार या विषम परिस्थितियों के बाद कदम उठाने के बजाय समितियां गठित कर दी जाती हैं। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद भी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा, 'सीडब्ल्यूसी ने चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन और ब्लॉक एवं जिला स्तर पर संगठनात्मक मुद्दों को लेकर आंतरिक समितियां गठित करने का फैसला लिया है'।

समस्या कमेटियों का गठन करने की भी नहीं है। बड़ी समस्या यह है कि उन कमेटियों की रिपोर्ट पर कभी बात नहीं होती और न ही उनकी अनुशंसाओं पर कोई कदम उठाये जाते हैं। आज खरगे कह रहे हैं कि हमें जिस भी राज्य में चुनाव हो, वहां एक साल पहले से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए और चुनाव मैदान में हमारी चुनाव मशीनरी समय से पहले सक्रिय हो जानी चाहिए। यही बात 2007 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाली कमेटी भी कर चुकी है। उसके बाद से लोकसभा के चार और विधानसभाओं के ढेर सारे चुनाव हो चुके हैं। मई, 2022 में जब सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष थीं, तब

उन्होंने 2024 के चुनाव से पहले पार्टी की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक हाई-प्रोफाइल 'एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप' का गठन किया था। पर 2022 और 2024 के बीच इस समूह की कोई बैठक हुई भी या नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उससे पहले अप्रैल, 2020 में सोनिया गांधी ने समकालीन मुद्दों पर पार्टी की लाइन तय करने के लिए 11 सदस्यीय परामर्श समूह गठित किया था। इस समूह की भी शायद ही कभी कोई बैठक हुई। इसी तरह सितंबर, 2020 में सोनिया गांधी ने संगठनात्मक फेरबदल करते हुए संगठन और संचालन मामलों में उनकी मदद करने के लिए छह सदस्यीय स्पेशल कमेटी गठित की थी, जिसमें ए.के। एंटनी, अहमद पटेल (अब दिवंगत), अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला थे। अहमद पटेल के स्थान पर किसी और को नियुक्त नहीं किया गया और फिर इस पूरी समिति को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया।

इससे पूर्व में भी बनीं कई समितियों की रिपोर्टें 24, अकबर रोड में धूल खा रही हैं। इनमें रामनिवास मिर्धा की संगठनात्मक चुनावों पर, मनमोहन सिंह की पार्टी फंड पर, पीए संगमा और सैम पित्रोदा की संगठन के आधुनिकीकरण पर और प्रणब मुखर्जी की संगठनात्मक मामलों पर रिपोर्ट शामिल हैं। इनके अलावा फ्यूचर चैलेंजेस ग्रुप (जिसमें एक सदस्य बतौर स्वयं राहुल गांधी शामिल थे) और एआईसीसी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग के दस्तावेज भी वहीं किसी ताक पर जमुहाइयां लेते मिल जायेंगे। वर्ष 2014 से 2019 के बीच विभिन्न चुनावों में पार्टी की पराजयों पर एके एंटनी की तीन रिपोर्टों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। मई, 2022 में उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था। उसमें कांग्रेस के करीब 150 नेताओं ने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की थीं, लेकिन वह रिपोर्ट भी जयराम रमेश के लैपटॉप से कभी बाहर नहीं निकल पायी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लगातार चिंता जताते आ रहे हैं। लेकिन अगर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो हो सकता है पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहने के औचित्य पर उनके भीतर से ही सवाल उठने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वह अपने पद पर लंबे समय तक शायद ही रहें। इन हालात में गांधी त्रयी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आज खरगे जो कह रहे हैं, उस पर अमल होना ही चाहिए। 'अभी नहीं तो कभी नहीं' के मिशन मोड पर आकर कदम उठाने चाहिए।

इस बीच, कांग्रेस के लिए एक अकेली अच्छी खबर यह आयी है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव जीतकर संसद में आ गयी हैं। वर्ष 2019 में प्रियंका ने जब से सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया है, तब से काफी काम किया है। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले ही 200 से ज्यादा बैठकें की थीं। लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, तो इसमें प्रियंका की कैंपेनिंग को भी श्रेय जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस नेतृत्व उनका इस्तेमाल किस तरह से कर पायेगा। क्या वह कांग्रेस की रणनीतिकार होंगी या अहमद पटेल की तरह पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच सेतु का काम करेंगी? अभी तक उनकी कोई भूमिका तय नहीं की गयी है, जबकि उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका में लाने का यही सबसे मुनासिब वक्त है।

संविधान से क्यों नहीं हटेगा सेकुलर शब्द?

राजेश चौधरी

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े जाने को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। इससे जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दी। 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन के जरिये प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए थे। इसे लेकर शीर्ष अदालत के सामने सवाल उठाए गए थे। इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट कई बार पहले भी व्यवस्था देते हुए कह चुका है कि सेकुलरिज्म संविधान का मूलभूत अंग है। संविधान की मूल प्रस्तावना में सेकुलर शब्द नहीं था। संविधान सभा में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तब संविधान की प्रस्तावना में 'संप्रभुतासंपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य' ही लिखा गया। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1976 में संशोधन के जरिये संविधान की प्रस्तावना में 'संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' लिखा गया। इसी संशोधन को अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते खारिज कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने मामले को लार्जर बेंच के पास भेजने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन करने का अधिकार है। उसे यह अधिकार अनुच्छेद-368 के तहत हासिल है। अदालत ने कहा कि 44 साल बाद संशोधन प्रक्रिया को अमान्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सेकुलरिज्म संविधान की मूलभूत विशेषता है। मूल रूप से, धर्मनिरपेक्षता का विचार समानता के अधिकार के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो संवैधानिक ढांचे के पैटर्न को दर्शाने वाले बुनियादी ताने-बाने में गहराई से बुना हुआ है। भारत ने समय के साथ धर्मनिरपेक्षता की अपनी व्याख्या विकसित की है, जिसमें राज्य न तो किसी धर्म का समर्थन करता है और न ही किसी धर्म का पालन और अभ्यास करने से मना करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय संदर्भ में समाजवाद का मतलब भी खास आर्थिक नीतियां अपनाने के लिए बाध्य करना नहीं है। समाजवाद का अर्थ सिर्फ इतना है राज्य की प्रतिबद्धता एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सभी नागरिकों को समान अवसर सुनिश्चित करने की है। केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में 1973 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की संविधानपीठ ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया था। कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ऐसे ही एस.आर. बोम्मई बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की आधारशिला है। आर.सी. पौड्याल बनाम केंद्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि शुरू से ही संविधान का अभिप्राय सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देने और उनके साथ बिना भेदभाव के व्यवहार करने का था। एम. इस्माइल फारूकी बनाम केंद्र सरकार मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता और सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्षता भारत की संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व है। इसे समानता के अधिकार का एक पहलू माना जाता है, जो संविधान की मूल संरचना के ताने-बाने में समाहित है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता रहा है कि प्रस्तावना में जिस तरह से सेकुलर व सोशलिस्ट शब्द संविधान संशोधन के जरिये डाले गए क्या उसी तरह से संविधान संशोधन के जरिये इन्हें हटाया भी जा सकता है?

संवैधानिक लोकतंत्र और भारत की आत्मा

योगेंद्र यादव

लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक उम्मीद की खिड़की खुली थी। संवैधानिक लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों के सामने जो दीवार खड़ी हुई थी, उसमें एक खिड़की खोलने का काम जनता ने किया था। इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव की तरह जनता ने 2024 में भी एक दीवार में खिड़की खोलकर विपक्षी पार्टियों को मौका दिया था कि वह इसे दरवाजा बना सकें, और उस रास्ते से देश बचाने की लड़ाई लड़ सकें। पर भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि अक्सर पार्टियां ऐसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पातीं। छह महीने के भीतर तीन विधानसभा चुनावों के बाद यह खिड़की सिकुड़कर एक रोशनदान भर रह गयी है। जिम्मेदारी अब फिर जनता और जन संगठनों पर आन पड़ी है कि वे भारतीय संविधान की आत्मा को बचाने का संघर्ष तेज करें।

रोशनी की इस खिड़की के जरिये दरवाजा खोलने के लिए जरूरी था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले धक्के को उसकी पराजय के सिलसिले में बदला जाए। लोकसभा के बाद के तीनों चुनावों में यह काम असंभव नहीं था। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहां विधानसभा का चुनाव जीता हुआ माना जा रहा था। हरियाणा में लोकसभा की सीटें पांच-पांच में बंटी थीं, पर विधानसभा के संदर्भ में यह मानना स्वाभाविक था कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। झारखंड में मामला कठिन था। चूंकि लोकसभा चुनाव

में भाजपा और सहयोगियों का पलड़ा भारी था, फिर भी लगता था कि कोशिश की जाये, तो झामुमो और सहयोगियों की जीत संभव है। वास्तव में हुआ इसका उलटा। जिस झारखंड में जीत सबसे कठिन थी, वहां इंडिया गठबंधन धड़ल्ले से जीता।

हरियाणा में जहां कांग्रेस को जीतना चाहिए था, वहां हार गयी। और जिस महाराष्ट्र में चुनाव जीता-जिताया लग रहा था, वहां इंडिया गठबंधन का सफाया हो गया। बेशक यह चुनाव परिणाम विवाद से परे नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र में विपक्ष ने चुनाव परिणाम पर उंगली उठायी है। पिछले 35 साल से चुनावी जीत-हार देखते हुए मुझे भी पिछले साल मध्य प्रदेश के आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम की तरह हरियाणा और महाराष्ट्र में दाल में कुछ काला दिखता है। एक बात तय है। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के जो तेवर ढीले पड़े थे, उसमें अब बदलाव आयेगा। इसका संकेत महाराष्ट्र की विजय के बाद संसद सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री के बयान से ही लग जाता है। अब भी भाजपा के लिए संविधान बदलना या संविधान बदलने जैसी 'वन नेशन-वन इलेक्शन' योजना लागू करना संभव नहीं हो पायेगा। पर बाकी एजेंडे पर सरकार आगे बढ़ेगी। चाहे वक्फ बोर्ड का कानून हो, समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव या जनगणना के जरिये डीलिमिटेशन, सभी दिशाओं में भाजपा तेजी से आगे बढ़ेगी। विरोध के स्वर को दबाने की कोशिशें भी तेज होंगी -चाहे सोशल मीडिया व यू ट्यूब पर फंदा कसने का मामला हो या जनांदोलनों व जन संगठनों को ठिकाने लगाने के कानून हों, या राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों पर बदले की कार्रवाई।

चंद औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां भी अब बेलगाम तरीके से बढ़ेंगी। पिछले कुछ महीनों में सेबी अध्यक्ष और गौतम अदाणी को लेकर जिन सवालों पर सरकार घिरती नजर आ रही थी, अब उन्हें दरकिनार किया जायेगा। अगले एक साल तक सत्तारूढ़ दल अपने हर निर्णय के लिए लोकप्रियता की दुहाई देगा। एनडीए में भाजपा का वजन बढ़ेगा और भाजपा में फिर मोदी जी का।

ऐसे में, संवैधानिक लोकतंत्र और भारत की आत्मा के लिए प्रतिबद्ध जन आंदोलनों, जन संगठनों और नागरिकों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। विपक्षी पार्टियों से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे संसद में सत्तारूढ़ पक्ष के गैर लोकतांत्रिक एजेंडे का विरोध करें, पर ऐसा नहीं लगता कि उनकी बात ज्यादा सुनी जायेगी। विपक्ष अगर दिल्ली और बिहार के चुनाव में भाजपा को रोक सका, तो यही उनका सबसे बड़ा योगदान होगा।आने वाले समय में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का असली मैदान संसद से ज्यादा सड़क होगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसान की अवस्था, दलित, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जैसे मुद्दे हैं, जिन पर जन संगठनों को खड़ा होना पड़ेगा।

अदाणी के घोटालों पर भी केवल विपक्ष के बोलने से काम नहीं चलेगा, जब तक सड़कों पर यह सवाल नहीं उठता है।पर संसद और सड़क से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मोर्चा है संस्कृति का। अंततः भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है। आजादी के आंदोलन ने भारत की जिस परिकल्पना को गढ़ा था, उसे बचाना और हर नयी पीढ़ी के लिए नये मुहावरे में समझाना सबसे बड़ा दायित्व है। सच यह है कि आजादी के बाद की पीढ़ियां इस दायित्व का निर्वाह ईमानदारी से नहीं कर पायी हैं। इसीलिए संविधान विरोधी और देश विरोधी विचार व राजनीति आज संवैधानिक सत्ता पर काबिज है। उसका मुकाबला तभी हो सकता है, जब हम संविधान की भाषा को जनता के मुहावरे और जनता के सरोकार से जोड़ें। संविधान निर्माण की 75 वीं वर्षगांठ पर यह उन सब नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, जो आज भी संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखते हैं। अब भी मौका है- खिड़की न सही, रोशनदान अब भी खुला है।

मंदिर-मस्जिद विवाद को हवा देना देश के लिए नुकसानदेह

शाजिया इल्मी

संभल में हुई आगजनी की घटना के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किए जाने तक निचली अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। अजमेर में एक स्थानीय अदालत द्वारा एक याचिका पर सुनवाई करने के निर्णय से एक अन्य धार्मिक फर्म को झटका लगने का खतरा है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका में सर्वेक्षण और अजमेर दरगाह पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार देने की मांग की गई है। याचिकाकर्त्ता, हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता, जिनके पास झूठी शिकायतों का एक लंबा इतिहास है, ने दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने का तर्क दिया है। काश गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के सरसंघचालक मोहन भागवत जी की बातों पर ध्यान दिया होता, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हर मस्जिद में 'शिवलिंग' खोजने और हर दिन एक नया विवाद शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

जून 2022 में, उन्होंने कहा था कि अब ज्ञानवापी मस्जिद (वाराणसी में) का मुद्दा चल रहा है। इतिहास है, जिसे हम बदल नहीं सकते। वह इतिहास हमने नहीं बनाया है, न ही आज के हिंदुओं या मुसलमानों ने। यह उस समय हुआ जब इस्लाम आक्रमणकारियों के साथ भारत में आया था। आक्रमण के दौरान, स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों के धैर्य को कमजोर करने के लिए मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। ऐसे हजारों मंदिर हैं। पिछले कुछ समय से अजमेर दरगाह कुछ कट्टरपंथी समूहों के लिए विवाद का विषय रही है। यह कुछ ऐसे लोगों द्वारा हास्यास्पद दावों का विषय रही है जो स्पष्ट रूप से सूफी विचारधारा के इतिहास और महत्व को नहीं समझते हैं। विडंबना यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पवित्र दरगाह को इक्षहदुओं द्वारा उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना मुसलमानों द्वारा। दरगाह बाजार में 75 प्रतिशत से अधिक दुकानें और होटल हिंदुओं के स्वामित्व में हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सभी प्रधानमंत्रियों ने उर्स के अवसर पर पवित्र चादर भेजी है।

बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी और संभल के विवादों

के बाद, अजमेर 2 समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के ताने-बाने पर सबसे नया तनाव है। हालांकि, जहां अन्य विवादित स्थल मस्जिद थे, वहीं यह एक प्रसिद्ध सूफी दरगाह है। मस्जिद और दरगाह के बीच मुख्य अंतरों में से एक यह है कि मस्जिद मुसलमानों के लिए इबादत की जगह होती है जहां आस्तिक सजदा करते हैं, यानी अल्लाह को सजदा करते हैं, जबकि दरगाह वह जगह होती है जहां श्रद्धेय सूफी संतों के लिए दरगाह बनाई जाती है। यह पहली बार नहीं है कि किसी सूफी दरगाह को खतरा पहुंचा है। सूफी संप्रदायों या सिलसिलों को रूढ़िवादी धर्मशास्त्र के विपरीत माना जाता है, यही कारण है कि सदियों से उन्हें सताया जाता रहा है।

सूफीवाद इस्लामी विचार का तपस्वी, रहस्यवादी रूप है, जिसके गूढ़ रूप सला-सुन्नी विभाजन से परे, राजनीतिक सीमाओं, आर्थिक वर्गों, भाषाओं और धर्मों तक फैले हुए हैं। अपने बढ़ते प्रभाव क्षेत्र से खतरे में पड़े सूफियों और उनकी दरगाहों पर धार्मिक इस्लामी विचार के सभी स्कूलों ने हमला किया है। वहाबी, देवबंदी, सलाफी और इस्लामी पुनरुत्थानवादी संतों और सूफी प्रथाओं की पूजा को बहुदेववादी मानते हैं। अफगानिस्तान और ईरान से लेकर तुर्की और आज के पाकिस्तान तक, सूफी संप्रदायों को अभी भी भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। भारत में भी देवबंदी संप्रदाय ने अक्सर दरगाह वालों की इक्षनदा की है, कई बार तो उन्हें धार्मिक वैधता देने से भी इंकार कर दिया है। यह मानना आसान है कि भारत में आखिरी सूफी शहीद सरमद काशानी को कट्टरपंथी औरंगजेब ने मरवा दिया था।अजमेर, जहां बादशाह अकबर ने 17 से ज्यादा बार यात्रा की थी, उनके पड़पौत्र दारा शिकोह का जन्मस्थान भी था, जो शाहजहां के उत्तराधिकारी थे। हालांकि, दारा शिकोह को 1659 में फांसी दे दी गई थी।

अपने भाई औरंगजेब के आदेश पर, बमुश्किल 2 साल बाद, दारा शिकोह के करीबी विश्वासपात्र सरमद का औरंगजेब के आदमियों ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सिर कलम कर दिया था। सरमद को ईशनिंदा के आरोप में फांसी दी गई थी, लेकिन उन्हें आज भी संत माना जाता है और जामा मस्जिद के पास उनकी मजार सूफी तीर्थयात्रा का एक प्रेरणादायक स्थान बनी हुई है। यद्यपि रहस्यवादी दारा शिकोह की महानतम साहित्यिक विरासत सिर-ए-अकबर या 'महान रहस्य' थी, जो उपनिषदों का फारसी अनुवाद था, यह उनका मजमा-उल-बहरीन या 'दो समुद्रों का संगम' था, जो एकता पर पहला ग्रंथ था, जिसने एक प्रबुद्ध सफलता में सूफीवाद और वेदांत के बीच समानता की खोज की। मोहन भागवत की सलाह को गंभीरता से सुनने के अलावा विष्णु गुप्ता जैसे लोग दारा शिकोह की इस अंतर्दृष्टि से भी सीख सकते हैं कि इस्लाम और हिंदू धर्म में कोई बुनियादी अंतर नहीं है।

उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक धर्म के विद्वान अपने-अपने धर्मों की संरचनाओं में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें इस एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सत्य का एहसास नहीं हुआ। शायद सबसे महत्वपूर्ण यह कि दोनों धर्म मूलतः एक ही हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि उन्हें इस महान अंतर्दृष्टि से अवगत कराया जाए। समावेशी विकास के पथ पर अग्रसर भारत सांप्रदायिक उथल-पुथल और व्यवधानों से मुक्त हो सकता है। धार्मिक संघर्ष सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास के विचार के विपरीत है। असभ्य धार्मिक द्वेष को रोकना होगा, इससे पहले कि यह हमारी सभ्यतागत लोकाचार की सहज आध्यात्मिकता को नष्ट कर दे। कल के भारत को अस्थिर और पटरी से उतारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हम बंगलादेशी हिंदुओं की व्यथा को हल्के में न लें

डॉ. वरिन्द्र भाटिया

1971 की भारत पाक जंग के बाद हिंदुस्तान की बदौलत वजूद में आए बंगलादेश में हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव हमारे देश के लिए निरंतर चिंता का सबब बना हुआ है। जनसंख्या के लिहाज से, बंगलादेश भारत और नेपाल के पड़ोसी देशों के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है। बंगलादेश के 64 जिलों में से 61 में हिंदू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन बंगलादेश में कोई भी हिंदू बहुल जिला नहीं है। वर्तमान बंगलादेश में हिंदू आबादी लगातार जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में घट रही है, 1941 में 28 प्रतिशत से 1971 में बंगलादेश की स्थापना के समय 13.5 प्रतिशत हो गई और 2022 में और कम होकर 7.9 प्रतिशत हो गई । बंगलादेश मुक्ति युद्ध के दौरान उत्पीडन् से बचने के लिए लगभग 80 लाख हिंदू भारत के विभिन्न हिस्सों में भाग गए। आजादी के बाद, यह पता चला कि 15 लाख हिंदू भारत में रह गए।

ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री अबुल बरकत के अनुसार, 1964 से 2013 तक धार्मिक उत्पीडन् और भेदभाव के कारण लगभग 11.3 मिलियन हिंदुओं ने बंगलादेश छोड़ दिया। उनके अनुसार औसतन हर दिन 632 हिंदू देश छोड़कर चले गए और सालाना 230,612 हिंदू देश छोड़कर चले गए। पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी नई नहीं है। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, लाखों की संख्या में हिन्दू और मुसलमानों ने धर्म के आधार पर मुल्क बदला। फिर भी कुछ मुसलमान ऐसे थे, जो भारत में ही रह गए और इसी तरह कुछ हिन्दू पाकिस्तान में रह गए। भारत ने हिन्दू राष्ट्र बनने की बजाय धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना पसंद किया, ताकि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित न समझें, उन्हें समान अधिकार मिलें और इसके लिए भारत ने अपने संविधान में धर्म चुनने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों की सूची में स्थान दिया है।

भारत विभाजन से पहले मुसलमानों की संख्या भारत की कुल आबादी का 10 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गई है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की किस्मत भारतीय मुसलमानों जैसी न तब थी, न आज है। पाकिस्तान में बसे हिन्दुओं में से लगभग 96 फीसदी सिंध प्रान्त में ही रहते हैं। वर्ष 1956 में पाकिस्तान का संविधान बना और पाकिस्तान प्रगतिशील और उदारवादी विचारधाराओं को त्यागकर कट्टर देश बन गया, और तभी से अल्पसंख्यक हिन्दुओं का वहां रहना दुश्वार हो गया। बंगलादेश में भी यह कहानी दोहराई जा रही है।देखने में आया है कि पाकिस्तान की जब भी भारत के आगे दाल नहीं गलती तो सभी घटनाओं का दुष्परिणाम पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं को भुगतना पड़ता है । जिया-उल-हक की तानाशाही से लेकर अब तालिबान के अत्याचारों तक पाकिस्तानी हिन्दुओं का जीवन दूभर ही रहा है।

कहते हैं कि आजादी के वक्त पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे, जिनमें से अब सिर्फ 26 ही बचे हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर हिन्दू मंदिर या गिरा दिए गए या उन्हें होटल बना दिया गया है। पाकिस्तान के नैशनल कमिशन फॉर जस्टिस एंड पीस की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक 74 प्रतिशत हिन्दू महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रान्त में हर महीने 20 से 25 हिन्दू लड़कियों का अपहरण होता है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जब पाकिस्तान में जीने के लिए हिन्दू अल्पसंख्यकों की अनुकूल स्थिति नहीं रही, तो बंगलादेश इसका अपवाद कैसे साबित होगा और आज यही कुछ हिंदुओं के साथ बंगलादेश में देखने को मिल रहा है।

बंगलादेश की वर्तमान सरकार भारत विरोधी सोच वाली है जिससे यूनुस भी अछूते नहीं हैं। अगर वे भारत हितैषी दिखना भी चाहें तो वह ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हसीना सरकार के गिरने का बड़ा कारण उनका भारत हितैषी नजरिया था। वरना वहां सुप्रीमकोर्ट का रिजर्वेशन पर फैसला आने के बाद उनको अपदस्थ करने का कोई कारण ही नहीं था? रिजर्वेशन के नाम पर वहां के युवाओं को हथियार के रूप में बंगलादेशी कट्टरपंथियों ने इस्तेमाल किया और हसीना सरकार को गिरा दिया। ये लोग ऐसे अवसर की तलाश में ही बैठे थे। खेद की बात है कि जिस बंगलादेश को आजाद कराने के लिए हिन्दुस्तानी यानी भारतीय फौजों ने मुकाबला किया था, इसी भारत के बहुसंख्यकों को अब वहां के हुक्मरान अपना दुश्मन क्यों मानते हैं?

ऐसे कीजिए प्रार्थना ईश्वर जल्द सुनेंगे

जब हम अंदर से भरपूर होते हैं, तब हमें किसी की भी कोई मदद की आवश्यकता नहीं रहती, परंतु ज्यों ही हमारा स्टॉक खत्म हो जाता है, त्यों ही हम एक असहाय बच्चे की तरह अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं।

संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य प्राणी नहीं होगा जो प्रार्थना न करता हो। अमीर, गरीब, छोटे,बड़े जो भी हैं, वे सभी प्रार्थना अवश्य करते हैं, मगर हममें से अधिकांश लोग दुःख की घड़ी में प्रार्थना ज्यादा करते हैं, इसलिए ही तो संत कबीर जी ने यह कहा है कि...

दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करै न कोय।
जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय॥

वास्तव में देखा जाए तो ऐसा ही है, क्योंकि जब हम अंदर से भरपूर होते हैं, तब हमें किसी की भी कोई मदद की आवश्यकता नहीं रहती, परंतु ज्यों ही हमारा स्टॉक खत्म हो जाता है, त्यों ही हम एक असहाय बच्चे की तरह अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं।

अनुभव के आधार परऐसा अनेक बार देखा गया है कि सच्चे हृदय से यदि भगवान की प्रार्थना की जाती है तो अपना इच्छित मनोरथ व कार्य जरूर पूरा होता है।

इसके पीछे का अध्यात्मिक रहस्य यह है कि प्रार्थना करने वाले को यह विश्वास रहता है कि परमात्मा ऐसा शक्तिशाली है कि वह आसानी से मेरी इच्छा को पूरा करेंगे ही। इसके साथ-साथ वह यह भी सोचता है कि मैं अपने अन्त-करण का श्रेष्ठतम भाग, श्रद्धा,विश्वास, परमात्मा पर आरोपण करते हुए सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा हूं।

इसलिए मेरी पुकार सुनी जाएगी। मनोचिकित्सकों के अनुसार कोई भी मनुष्य जब अपनी मानसिक स्थिति ऐसी बना ले कि मेरा मनोरथ सफल होने की पूरी आशा, पूरी संभावना है ही, तो अधिक मौकों पर उसके मनोरथ पूरे हो ही जाते हैं, क्योंकि आशा और संभावनामयी मनोदशा के कारण मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियां असाधारण रूप से जाग उठती हैं जिसके फलस्वरूप सफलता का मार्ग बहुत आसान बनता जाता है और प्राय-वह प्राप्त भी हो जाता है।

परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणी एक समान हैं, अत- वे समदर्शी कहलाते हैं। किंतु उस समदर्शी को भी विवश होकर एक बार यह कहना पड़ा कि समदर्शी मोहि कह सबकोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥

अर्थात सभी मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझे सेवक प्रिय हैं, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। इसीप्रकार से विष्णु चतुर्भुज की प्रार्थना में जब भक्तयह कहते हैं कि

अविनयमपनय विष्णो दमयमनशमय विषयमृगतृष्णाम।
भूतदयां विस्तारयतारय संसारसागरत

तब उनकी यह प्रार्थना में कितनी श्रद्धा, विश्वास एवं नम्रता दिखती हैं। अब ऐसा कौन मनुष्य होगा जो इस नम्रता परन पिघल उठे? यह तो फिर उस महान विभूति के लिये प्रयुक्त है जो अपनी दयालुता के लिए दया सागर के नाम से विख्यात हैं।

इस प्रार्थना के बाद क्या कोई चिन्ता, दुःख द्वेषादि टिक सकते हैं? बिलकुल नहीं! गीता में प्रभु स्वयंजब यह गारंटी देते हैं कि जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मान कर अनन्य-भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य-कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरन्तर मेरी भक्ति में लीनरहता है उस मनुष्य की सभी आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूं,तो फिर उसे न मानने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

परमात्मा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें- यहां वहां हाथ फैलाने से बेहतर हैं की हम उस एक परमात्मा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी हर समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए केवल उस एक सर्व शक्तिमान के सामने अपना माथा टेकें। सच्चे हृदय से यदि ईश्वर की प्रार्थना की जाएतो भक्तों की हर इच्छा व मनोरथ वह जरूर पूरी करते हैं।

बड़े ही विचित्र तरीके से हुआ था राधा का जन्म

पुराणों में वर्णित है कि एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्रीदामा नामक गोप में विवाद हो गया। श्रीराधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। तब उस गोप ने भी श्रीराधा को यह श्राप दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहां गोकुल में श्रीहरि के ही अंश महायोगी रायाण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायाण की पत्नी ही समझेंगे, श्रीहरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु के श्रीकृष्ण अवतार का समय आया तो उन्होंने राधा से कहा कि तुम जल्द ही वृषभानु के घर जन्म लो। श्रीकृष्ण के कहने पर ही राधा ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुईं। राधा देवी अयोनिजा यानी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थीं उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योगमाया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया परंतु वहां स्वेच्छा से श्रीराधा प्रकट हो गई।

तीर्थ यात्रा करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए ये 5 बातें

तीर्थ दर्शन की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। मान्यता है कि तीर्थ यात्रा से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप भी किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हैं तो यहां जानिए 5 ऐसी बातें जो यात्रा में ध्यान रखना चाहिए

- तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए। अन्यथा वह रोग एवं दोष का भागी होता है।
- अन्यत्र हिकृतं पापं तीर्थ मासाद्य नश्यति। तीर्थेषु यत्कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि किसी दूसरी जगह किया हुआ पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप कभी नष्ट नहीं हो पाता है। अत : तीर्थ क्षेत्र में कोई अधार्मिक कर्म नहीं करना चाहिए।
- जब कोई व्यक्ति अपने माता-पिता, भाई, परिजन अथवा गुरु को पुण्य फल दिलवाने के उद्देश्य से तीर्थ में स्नान करता है, तब स्नान करने वाले व्यक्ति को पुण्य फल का बारहवां भाग प्राप्त होता है।
- जो व्यक्ति दूसरों के धन से तीर्थ यात्रा करता है, उसे पुण्य का सोलहवां भाग प्राप्त होता है।
- जो व्यक्ति किसी दूसरे कार्य से तीर्थ में जाता है तो व्यक्ति को तीर्थ जाने का आधा पुण्य फल प्राप्त होता है।

इस कारण स्त्रियां कभी नहीं फोड़ती है नारियल!

नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है की जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो वे अपने साथ तीन चीजें- लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष तथा कामधेनु लाए इसलिए नारियल के वृक्ष को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी अर्थात नारियल लक्ष्मी व विष्णु का फल। नारियल में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। श्रीफल भगवान शिव का परम प्रिय फल है। मान्यता अनुसार नारियल में बनी तीन आंखों को त्रिनेत्र के रूप में देखा जाता है। श्रीफल खाने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। इष्ट को नारियल चढ़ाने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भारतीय पूजन पद्धति में नारियल अर्थात श्रीफल का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी वैदिक या दैविक पूजन प्रणाली श्रीफल के बलिदान के बिना अधूरी मानी जाती है। यह भी एक तथ्य है कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़तीं। श्रीफल बीज रूप है, इसलिए इसे उत्पादन अर्थात प्रजनन का कारक माना जाता है। श्रीफल को प्रजनन क्षमता से जोड़ा गया है। स्त्रियों बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं और इसलिए नारी के लिए बीज रूपी नारियल को फोड़ना अशुभ माना गया है। देवी-देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष ही इसे फोड़ते हैं। शनि की शांति हेतु नारियल के जल से शिवलिंग पर रुद्रभिषेक करने का शास्त्रीय विधान भी है। भारतीय वैदिक परंपरा अनुसार श्रीफल शुभ, समृद्धि, सम्मान, उन्नति और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। किसी को सम्मान देने के लिए उनी शॉल के साथ श्रीफल भी भेंट किया जाता है। भारतीय सामाजिक रीति-रिवाजों में भी शुभ शगुन के तौर पर श्रीफल भेंट करने की परंपरा युगों से चली आ रही है। विवाह की सुनिश्चित करने हेतु अर्थात तिलक के समय श्रीफल भेंट किया जाता है। बिदाई के समय नारियल व धनराशि भेंट की जाती है। यहां तक की अंतिम संस्कार के समय भी चिता के साथ नारियल जलाए जाते हैं। वैदिक अनुष्ठानों में कर्मकांड में सूखे नारियल को वेदी में होम किया जाता है।

श्रीफल कैलोरी से भरपूर होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं। इसके कोमल तनों से जो रस निकलता है उसे नीरा कहते हैं उसे लज्जतदार पेय माना जाता है। सोते समय नारियल पानी पीने से नाड़ी संस्थान को बल मिलता है तथा नींद अच्छी आती है। इसके पानी में पोटेशियम और क्लोरीन होता है जो मां के दूध के समान होता है। जिन शिशुओं को दूध नहीं पचता उन्हें दूध के साथ नारियल पानी मिलाकर पिलाना चाहिए। डि-हाइड्रेशन होने पर नारियल पानी में नीबू मिलाकर पिया जाता है। इसकी गिरी खाने से कामशक्ति बढ़ती है। मिश्री संग खाने से गर्भवती स्त्री की शारीरिक दुर्बलता दूर होती है तथा बच्चा सुंदर होता है।

घर के नजदीक हो ये पेड़-पौधे तो अवश्य करें पूजा होते हैं ढेरों लाभ

प्राचीनकाल से सनातन संस्कृति में पेड़-पौधों का पूजन होता आया है। ज्योतिष और वास्तु विद्वान भी मानते हैं की इनके पूजन करने से जीवन में आ रही बहुत सारी बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। कुछ ऐसे पेड़-पौधे होते हैं, जिन्हें घर में अवश्य रोपित करना चाहिए। यदि आपके घर में स्थान न हो तो आसपास भी ये दिखें तो अवश्य इनका पूजन करें। इससे आपको ढेरों लाभ प्राप्त होंगे।

तुलसी

विष्णु प्रिया हर हिंदू घर में विराजित होनी चाहिए। यदि आपके घर में नहीं हैं तो आज ही ले आएं। सुबह-शाम इन्हें जल अर्पित कर दीपदान करना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है वहां कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहता।

पीपल

इस पेड़ को घर में नहीं लगाना चाहिए और न ही इसकी छाया आपके आशियाने पर पड़नी चाहिए। घर से थोड़ी दूरी पर रोपित इस पेड़ का पूजन अवश्य करें। पीपल को जल से सींचने पर सभी पापों का जहां नाश हो जाता है वहीं पितर भी प्रसन्न होकर जीव पर कृपा करते हैं।

बिल्व

भगवान शिव के प्रिय बिल्व वृक्ष को काटने से वंश का अंश समाप्त हो जाता है और उसे लगाने से वंश में वृद्धि होती है। बिल्व पत्र के अभाव में शिव पूजा अधूरी रहती है। नौकरी में प्रमोशन पानी हो या दुख-दर्द से छुटकारा, करें इस पेड़ की पूजा।

केला

घर में केले का पेड़ ईशान कोण में लगाने से धन वृद्धि होती है। यदि इसके साथ तुलसी का पौधा भी रोपित कर दिया जाए तो घर-परिवार पर श्रीविष्णु-लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है।

बरगद

बरगद का पूजन करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि सदा बनी रहती है।

आंवला

प्रतिदिन इसका पूजन करने से जाने-अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है।

शमी

घर में शमी का पेड़ लगाने से दैवीय कृपा बनी रहती है।

अशोक

ये पेड़ जीवन से हर शोक का नाश करता है। जो लोग प्रतिदिन अशोक के पेड़ पर जल अर्पित करते हैं उन पर दैविय कृपा बनी रहती है। उन्हें बीमारी, दुख, अशान्ति जैसी चिंताएं छू भी नहीं पाती।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिल्ली में कांग्रेस के लिए केजरीवाल ने बंद किए दरवाजे

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। यह साफ तौर पर विपक्षी इंडिया गुट के लिए बड़ा झटका। केजरीवाल की यह घोषणा ऐसे समय आई है जब अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों से पहले राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। पहले ही, कई हाई-प्रोफाइल दलबदल हो चुके हैं, जिनमें कई कांग्रेस और भाजपा नेता आप में शामिल हो गए हैं। केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि आप दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं करेगी। वहीं, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा कर तोड़ सकता है उस पर दिल्ली का विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ये लोग अभी आपस में मोल भाव कर रहे हैं। ये एक दूसरे को धमकी देकर डराएंगे भी और मोल-भाव भी करेंगे।

मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे ने फिर किया दावा

मुंबई। एकनाथ शिंदे मुंबई लौट आए हैं, जिससे सत्ता-साझाकरण संबंधी चर्चाओं को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जो रुकी हुई थीं। कथित तौर पर नई सरकार में गृह मंत्रालय आवंटित नहीं किए जाने से नाराज कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने इन खबरों को खारिज नहीं किया है। उन्होंने टिप्पणी की कि इस मामले पर गठबंधन के तीन दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच एक बैठक में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि नई सरकार का शपथ ग्रहण होना बाकी है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के जीत के एक सप्ताह से अधिक समय बाद 2 या 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में फड़णवीस को विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। वहीं, शिंदे को इंडियन एक्सप्रेस में एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं जनता का मुख्यमंत्री था। दरअसल, मैं कहता था कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आम आदमी हूं।

संजय सिंह ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दायर किया

नईदिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, जिसे देखते हुए अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नोटिस दायर कर दिया है। संजय सिंह ने सोमवार को नियम 267 के तहत राज्यसभा में बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दायर किया है। इस नोटिस में राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराधों से संबंधित बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने की मांग की गई। संजय सिंह ने राज्यसभा महासचिव को सौंपे गए प्रस्ताव में लिखा, मैं आपका ध्यान देश की राजधानी में बढ़ते अपराधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राजदूत और दोनों सदनों के सांसद सभी दिल्ली में रहते हैं। देश की राजधानी अपराध की राजधानी बन गई है। संजय सिंह ने इससे पहले 29 नवंबर को भी एक कार्य स्थगन नोटिस दायर किया था जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती अपराध दर पर चर्चा की मांग की गई थी। सिंह ने नोटिस में कहा, 2024 के प्रमुख समाचार पत्रों के आंकड़े राजधानी में अपराध की चिंताजनक स्थिति को उजागर करते हैं।

अवध ओझा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल

नई दिल्ली। यूपीएससी शिक्षक और प्रेरक वक्ता अवध ओझा सोमवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। वह आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और केजरीवाल ने पार्टी की टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। अवध ओझा देश के सबसे प्रशंसित शिक्षकों में से एक हैं। उनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। वह एक भारतीय यूपीएससी कोच, यूट्यूबर और शिक्षक हैं। वह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से हैं। यूपीएससी परीक्षा में असफलताओं का सामना करने के बाद, उन्होंने इलाहाबाद में कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना शुरू किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अवध ओझा के आप में शामिल होने से पार्टी को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब आप को उस समय बड़ा झटका लगा जब पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया।

राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर : नितिन गडकरी

मुंबई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति को असंतुष्ट आत्माओं का समुद्र बताया। उन्होंने कहा कि यहां सभी लोग दुखी है और अपनी वर्तमान स्थिति से ऊंचे पद की इच्छा रखते हैं। नागपुर में अपनी किताब 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ (जीवन के 50 स्वर्णिम नियम) के लॉन्च के अवसर पर उन्होंने बताया कि जीवन समझौतों, मजबूरियों, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि व्यक्ति चाहे पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या कॉर्पोरेट में हो, उसका जीवन चुनौतियों से भरा रहता है। समस्याओं का सामना करने के लिए व्यक्ति को जीवन जीने की कला आनी चाहिए। राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम को याद किया, जहां उन्होंने कहा था, राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का समुद्र है, जहां सभी लोग दुखी हैं। जो पार्षद बनता है वह इस बात से दुखी होता है कि उसे विधायक बनने का मौका नहीं मिला।

संसद में जारी रहा विपक्ष का हंगामा, नहीं हो सका कोई बड़ा कामकाज

नईदिल्ली। लोकसभा और राज्यसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार को शीतकालीन सत्र का एक और दिन ऐसा था जहां कोई बड़ा कामकाज नहीं हुआ। विपक्षी सांसद संभल हिंसा और अमेरिका द्वारा गौतम अडानी को दोषी ठहराए जाने पर बहस की मांग करते रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से पहले भारत-चीन सीमा समझौते पर लोकसभा में बयान देने की उम्मीद थी। हालांकि, यह नहीं हो सका। विपक्ष और सत्तापक्ष संसद नहीं चलने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। आखिर संसद बना किस लिए है? समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि चर्चा हो। हम चर्चा की मांग करते रहेंगे क्योंकि सदन इसी के लिए होता है।

लोकसभा की कार्यवाही

विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक सोमवार को एक बार के स्थगन के बाद पुन: शुरू होने के करीब आठ मिनट के अंदर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य पिछले सप्ताह की तरह ही आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस सदस्य अदाणी समूह से जुड़े मामले को उठा रहे थे, वहीं सपा सांसद संभल हिंसा का मुद्दा उठाते देखे गए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच ही कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। बिरला ने इस दौरान नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा, ''प्रश्नकाल आपका समय है। कृपया प्रश्नकाल चलने दें और अपनी-अपनी सीट पर विराजें।'' बिरला के बार-बार अपील करने के बाद भी आसन के समीप खड़े कांग्रेस और सपा सांसदों की नारेबाजी जारी रही।

तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाला एक विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत

विपक्षी दलों के सदस्य अदाणी समूह से जुड़े मुद्दे और संभल हिंसा से संबंधित मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे।

राज्यसभा की कार्यवाही

अदाणी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, उत्तर प्रदेश के संभल और मणिपुर में हिंसा व कानून व्यवस्था की स्थिति सहित कुछ अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग खारिज होने के बाद सोमवार को विपक्ष ने राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। इसी दौरान द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के तिरूची शिवा ने अपनी बात रखने के लिए आसन से अनुमति मांगी। सभापति ने कहा कि यदि हंगामा कर रहे सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले जाएं और शांति बनाए रखें तो वह उन्हें अनुमति देंगे। लेकिन हंगामा जारी देख उन्होंने कुछ ही देर में कार्यवादी दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

मेरे दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले हैं, विरोध प्रदर्शन के बीच बोले उपराष्ट्रपति धनखड़

नईदिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और उनसे चर्चा और संवाद के माध्यम से उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक खुला और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती के अवसर पर एक समारोह में बोलते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सभा को याद दिलाया कि भारत की ताकत इसकी ग्रामीण जड़ों और इसके किसानों में निहित है, जो देश के विकास का आधार हैं। धनखड़ ने किसानों से टकराव के बजाय रचनात्मक बातचीत के माध्यम से अपने मुद्दों को हल करने का आग्रह किया और आपसी समझ के महत्व पर जोर दिया, इस बात पर जोर दिया कि उनके संघर्ष समृद्ध भारत की बड़ी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि हम अपनों से नहीं लड़ते, हम अपनों को धोखा नहीं देते। धोखा दुश्मन के लिए होता है, जबकि अपने गले लगाना होगा। जब किसानों के मुद्दों का तेजी से समाधान नहीं हो रहा है तो कोई चैन से कैसे सो सकता है? धनखड़ ने किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए पहले से ही चर्चा में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री शिवराज चौहान की भी सराहना की। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार सक्रिय रूप से समाधान पर काम कर रही है, लेकिन उनसे तेजी से समाधान के लिए रचनात्मक बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। धनखड़ ने कहा कि हमें खुले तौर पर सोचने और खुली चर्चा में शामिल होने की जरूरत है क्योंकि यह देश हम सभी का है। उन्होंने टकरावपूर्ण रवैये को खत्म करने और कूटनीति और आपसी सम्मान की वकालत करने का आह्वान किया। उन्होंने असाध्य और टकरावपूर्ण रुख को खराब कूटनीति करार देते हुए इस बात पर जोर दिया, हमें खुले तौर पर सोचने और खुली चर्चा में शामिल होने की जरूरत है क्योंकि यह देश हमारा है।

ओम बिरला संग सर्वदलीय बैठक के बाद संसद में गतिरोध खत्म

सुचारू कामकाज की उम्मीद, संविधान पर होगी बहस

नईदिल्ली। संसद में केंद्र और विपक्ष के बीच एक बड़ी सफलता में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में संविधान पर बहस आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। लोकसभा में 13 और 14 नवंबर और राज्यसभा में 16 और 17 नवंबर को बहस होगी। संसदीय गतिरोध का अंत तब हुआ जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक में कुछ दिनों से सदन में जो गतिरोध बना हुआ था उस पर सबने चिंता व्यक्त की।

रिजिजू ने कहा कि हमने भी कहा कि सदन में सब अपना बात रखने के लिए आते हैं सदन इतने दिनों तक नहीं चलना और जनता के पैसों का इतने दिन तक नुकसान होना ये ठीक नहीं है सबने इस बात को माना है और विपक्ष की ओर से भी कई मांग रखे गए। उन्होंने कहा कि व्यापार सलाहकार समिति में संविधान पर चर्चा होने का जो प्रस्ताव था उस पर सरकार ने मंजूरी दी है। 13 और 14 तारीख को संविधान पर चर्चा होगी। पहले लोकसभा में चर्चा करेंगे और 16-17 को राज्यसभा में चर्चा होगी। कल से चर्चा शुरू होगी और कल हम सदनों में पहला बिल पास करेंगे।

टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक पर कहा कि आज की बैठक में हम सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि सदन कल से शुरू होगा। 13-14 को संविधान पर चर्चा होगी। कल समाजवादी पार्टी को संभल पर बोलने की अनुमति दी जाएगी और हम बांग्लादेश पर बोलेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि विपक्ष संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर दो दिवसीय चर्चा चाहता है। हम सरकार के औपचारिक बुलेटिन का इंतजार कर रहे हैं, आज उन्होंने अनौपचारिक रूप से हमें बताया कि जल्द ही तारीख की घोषणा की जाएगी।

शिवसेना (यूबीटी) नेता अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक पर कहा कि यह तय हुआ है कि कल से सदन को ठीक से चलाया जाएगा और फिर 13-14 तारीख को भारत के संविधान पर चर्चा होगी। सभी इस पर सहमत हुए। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक पर कहा कि हमारा रुख सकारात्मक है लेकिन हम संभल के लोगों पर हो रहे अत्याचार और शोषण को स्वीकार नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि कल हमें इस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। उन्होंने (स्पीकर ओम बिरला) हमें आश्वासन दिया है। जिस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बेहतर होगा कि संविधान पर चर्चा हो।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत ने ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 को दी मात

कैनबरा। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 को कैनबरा के मनुका ओवर में 2 दिवसीय अभ्यास मैच में 6 विकेट से मात दी। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। वह मिडिल ऑर्डर में खेले। वहीं शुभमन गिल ने अपना फिफ्टी जड़ा। वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की।

हालांकि, इस दौरान विराट कोहली और ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी नहीं की। जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सैम कोनस्टास ने शतक जड़कर प्रभावित किया। पहला दिन शनिवार को बारिश के कारण बाधित रहा। टॉस तक नहीं हो सका। दूसरे और अंतिम दिन रविवार को भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

50-50 ओवर का मैच बारिश के कारण 46-46 ओवर का हुआ। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 ने 43.2 ओवर में 240 रन बनाए। सैम कोनस्टास ने 97 गेंद पर 107 रन बनाए। हेन्नो जैकब्स ने 59 गेंद पर 61 रन ठोके। जैक क्लेटन ने 40 रन की पारी खेली। तो भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 4, आकाशदीप ने 2, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा ने 1-1 विकेट की सफलता हासिल की। वहीं भारत की पारी की बात करें तो, टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 256 रन बनाए। 17 रन की बढ़त हासिल की। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल 45 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल 27 और शुभमन गिल 50 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। उन्होंने 3 रन बनाए। नितीश रेड्डी 42 और रविंद्र जडेजा 27 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज खान 1 रन बनाकर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर 43 और देवदत्त पडिक्कल 3 रन बनाकर नाबाद रहे। चार्ली एंडरसन ने 2, लॉयड पोप, मैट रेनशॉ और जैक क्लेटन को 1-1 विकेट मिला।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 445 अंक चढ़कर 80 हजारी हुआ

नईदिल्ली। ब्लू-चिप शेयरों रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस और एचडीएफसी बैंक में खरीदारी के बीच हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को लगातार दूसरे सत्र में भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स शुरुआती गिरावट से भी उभरते हुए करीब 446 अंक चढ़कर एक बार फिर से 80 हजार के पार निकल गया। निफ्टी 50 में जी तेजी देखी गई। 30 शेयरों वाला, बीएसई सेंसेक्स 445.29 अंक या 0.56 प्रतिशत की शानदार बढ़त लेकर 80,248.08 पर बंद हुआ। इससे पहले, यह इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 493.84 अंक की गिरावट क साथ 79,308.95 अंक पर आ गया। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 80,337.82 की ऊंचाई तक पहुंचा था। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 144.95 अंक या 0.6 प्रतिशत मजबूत होकर 24,276.05 पर बंद हुआ।

एमपीसी की बैठक 4-6 दिसंबर के बीच

नई दिल्ली। जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 5.4 प्रतिशत रहने के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) इस सप्ताह अपनी समीक्षा बैठक के दौरान मौजूदा रेपो दर को बरकरार रख सकता है। मई 2022 से, आरबीआई ने फरवरी 2023 तक रेपो दर को 250 बीपीएस बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया था, उसके बाद पिछली एमपीसी बैठक तक इसे स्थिर रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में एमपीसी की अगली बैठक 4 से 6 दिसंबर 2024 के बीच होनी वाली है। इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दास 6 दिसंबर को देंगे। महंगाई के आंकड़े सार्वजनिक होने से पहले बड़े पैमाने पर विशेषज्ञ अनुमान जता रहे थे कि अगली एमपीसी बैठक में बेंचमार्क दरों को कम किया जा सकता है।

कोटक म्युचुअल फंड के दो एनएफओ खुल

नईदिल्ली। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक महिंद्रा म्युचुअल फंड ने इक्विटी कैटेगरी में दो नए इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं। म्युचुअल फंड हाउस के एनएफओ कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और कोटक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का सब्सक्रिप्शन 2 दिसंबर से खुल गया है। इन ओपन एंडेड स्कीम्स में निवेशक 16 दिसंबर 2024 तक इन स्कीम्स में खरीद कर सकते हैं। म्युचुअल फंड हाउस के मुताबिक, कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में मिनिमम 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। इस स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 इक्वल वेटेड टीआरआई है। देवेन्द्र सिंघल स्कीम के फंड मैनेजर हैं। म्युचुअल फंड हाउस के मुताबिक, ऐसे निवेशक जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस फंड का रिटर्न निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स की परफॉर्मेंस के अनुरूप होगा, जो ट्रैकिंग एरर के अधीन है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पड़ी सुस्त

नईदिल्ली। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर 56.5 पर आ गई। ऑर्डर में धीमी वृद्धि के बीच प्रतिस्पर्धी स्थितियों और मुद्रास्फीति के दबावों के कारण वृद्धि सीमित रही। सोमवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। मौसमी रूप से समायोजित 'एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक' (पीएमआई) अक्टूबर में 57.5 था जो नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर 56.5 पर आ गया। पीएमआई के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है। एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा, ''भारत में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर नवंबर में 56.5 रही जो पिछले महीने से थोड़ी कम है, लेकिन अब भी विस्तार के दायरे में है।''

भारतीय आर्थिक दर्शन एवं प्राचीन भारत में आर्थिक विकास

प्रह्लाद सबनानी

भारत में वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में यह कहा गया है कि मानव जीवन हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों का करना आवश्यक है। अच्छे कर्म अर्थात हमारे किसी कार्य से किसी पशु, पक्षी, जीव, जंतु को कोई दु:ख नहीं पहुंचे एवं सर्व समाज की भलाई के कार्य करते रहें। अर्थात, इस धरा पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, मंगल हो। ऐसी कामना भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में की जाती है।

इसी प्रकार, धर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए कौटिल्य के अर्थशास्त्र, नारद की नारद स्मृति और याग्वल्य की याग्वल्य स्मृति में कहा गया है कि 'अर्थशास्त्रास्तु बलवत धर्मशास्त्र नीतिस्थिति'। अर्थात, यदि अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं नैतिकता के सिद्धांत के बीच कभी विवाद उत्पन्न हो जाए तो दोनों में से किसे चुनना चाहिए। कौटिल्य, नारद एवं याग्वल्य कहते हैं कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की तुलना में यानी केवल पैसा कमाने के सिद्धांतों की तुलना में हमको धर्मशास्त्र के सिद्धांत अर्थात नैतिकता, संयम, जिससे समाज का भला होता हो, उसको चुनना चाहिए। कुल मिलाकर अर्थतंत्र धर्म के आधार पर चलना चाहिए। गुनार मृडल जिनको नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था एवं जिनकी 'एशियन ड्रामा' नामक पुस्तक बहुत मशहूर हुई थी। उन्होंने एक और छोटी किताब लिखी है जिसका नाम है 'अगेन्स्ट द स्ट्रीम'। इस किताब में उन्होंने अर्थशास्त्र को एक नैतिक विज्ञान बताया है। कुछ वर्ष पूर्व अखबारों में एक खबर छपी थी कि विश्व बैंक ने यह जानने के लिए एक अधय्यन प्रारम्भ किया है कि विकास में आध्यात्म की कितनी भूमिका है। इसी प्रकार दुनिया में यह

जानने का प्रयास भी किया जा रहा है कि दरिद्रता मिटाने में धर्म की क्या भूमिका हो सकती है।

प्राचीन भारत के वेद-पुराणों में धन अर्जित करने को बुरा नहीं माना गया है। प्राचीन काल में वेदों का एक भाष्यकार हो गया है, जिसका नाम यासक था। यासक ने 'निघंटू' नामक ग्रंथ में धन के 28 समानार्थ शब्द बताए हैं, और प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है। दुनिया की किसी पुस्तक में अथवा किसी अर्थशास्त्र की किताब में धन के 28 समानार्थ शब्द नहीं मिलते हैं। भारत के शास्त्रों में धन के सम्बंध में उच्च विचार बताए गए हैं। भारत के शास्त्रों ने अर्थ के क्षेत्र को हेय दृष्टि से नहीं देखा है एवं यह भी कभी नहीं कहा है कि धन अर्जन नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए, उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहिए। बल्कि दरिद्रता एवं गरीबी को पाप बताया गया है। हां, वेदों में यह जरूर कहा गया है कि जो भी धन कमाओ वह शुद्ध होना चाहिए। 'ब्लैक मनी' नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार करके धन नहीं कमाना चाहिए, स्मग्लिंग करके धन नहीं कमाना चाहिए, कानून का उल्लंघन करते हुए धन अर्जन नहीं करना चाहिए, ग्राहक को धोखा देकर धन नहीं कमाना चाहिए। मनु स्मृति में तो मनु महाराज ने कहा है कि सब प्रकार की शुद्धियों में सर्वाधिक महत्व की शुद्धि अर्थ की शुद्धि है। भारतीय शास्त्रों में खूब धन अर्जन करने के बाद इसके उपयोग के सम्बंध में व्याख्या की गई है। अर्जित किए धन को केवल अपने लिए उपभोग करना, उस धन से केवल ऐय्याशी करना, केवल अपने लिए काम में लेना, अपने परिवार के लिए मौज मस्ती करना, आदि को ठीक नहीं माना गया है। अर्जित किए गए धन को समाज के साथ मिल बांटकर, समाज के हितार्थ उपयोग करना चाहिए। भारत के प्राचीन ग्रंथों में जीवन के उद्देश्य को पुरुषार्थ से जोड़ते हुआ यह कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों बातों पर विचार करके मनुष्य को सुखी करने के सम्बंध में विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के चलते भारत के मनीषियों द्वारा अर्थ और काम को नकारा नहीं गया है। कई बार भारत के बारे में वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जाता रहा है कि भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में तो अर्थ और काम को नकार दिया गया है। प्राचीन काल में भी ऐसा कतई नहीं हुआ है। अगर, ऐसा हुआ होता तो भारत सोने की चिड़िया कैसे बनता? **क्रमश: ...**

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.